

HARYANA VIDHAN SABHA

**THE SUBJECT COMMITTEE
ON
FOOD AND SUPPLIES**

(2016-2017)

(SECOND REPORT)

ON

**FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT,
HARYANA**

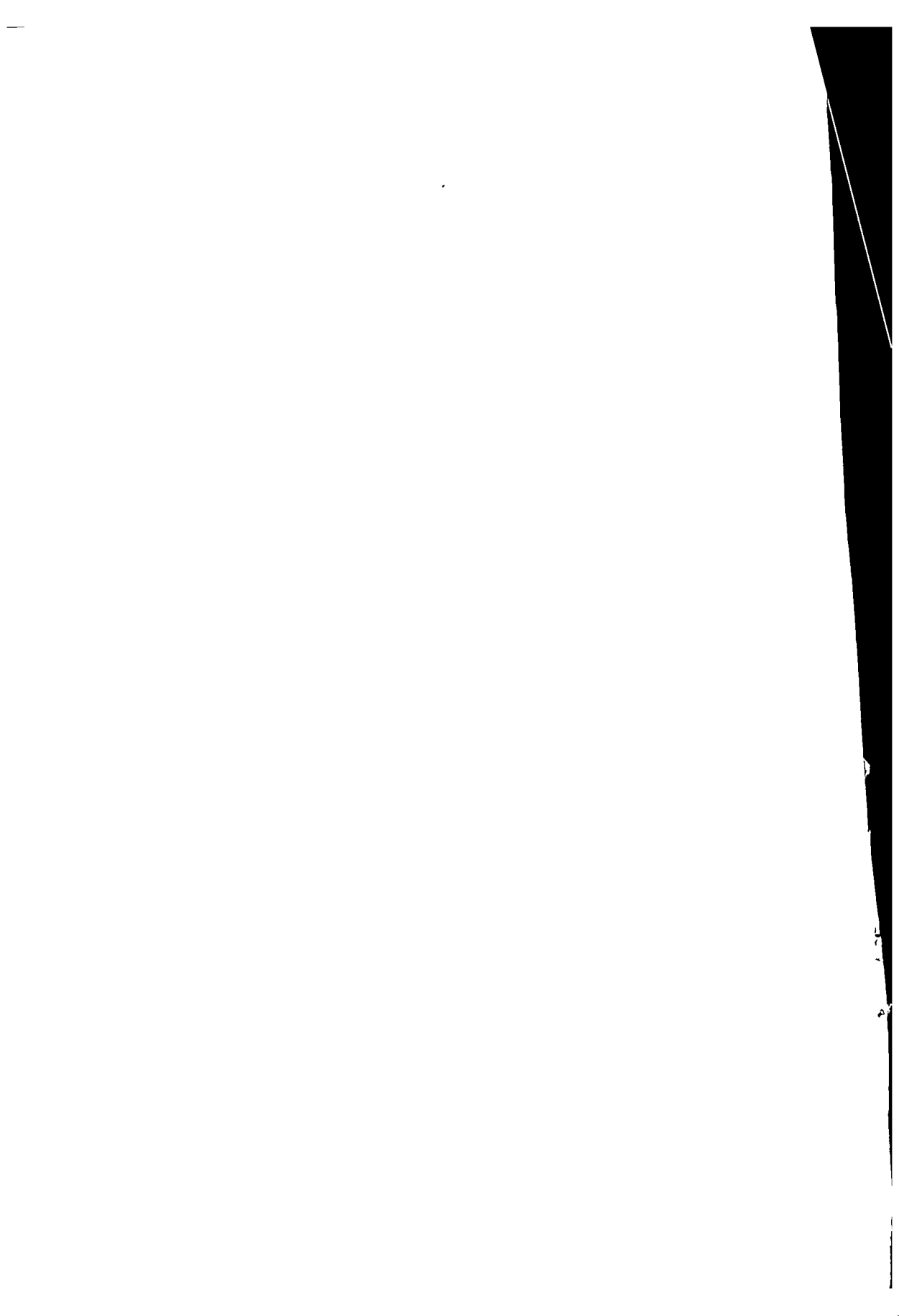


(Presented to the Haryana Vidhan Sabha on *10th* March, 2017)

**HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT
CHANDIGARH
2017**

TABLE OF CONTENTENTS

	Pages
Composition of the Committee	(iii)
i) Introduction	(v)
ii) Report	1
iii) Scope and function of the Committee	2
iv) Food and Supplies Department	3-68
v) Observations/Recommendation of the Committee	69



(iii)

**COMPOSITION OF THE COMMITTEE
THE SUBJECT COMMITTEE ON FOOD & SUPPLIES
2016-2017**

CHAIRPERSON

- * 1. Shri Vipul Goel, MLA

Members

2. Shri Prithi Singh, M L A
*** 3. Shri Bikram Singh Yadav, MLA
** 4. Dr. Pawan Saini, M L A
5. Shri Sukhvinder Singh, MLA
6. Shri Bhagwan Dass Kabir Panthi, M L A.
7. Shri Om Parkash Barwa, M.L A
8. Shri Bishamber Singh Balmiki, M L A
**** 9. Shri Mahipal Dhanda, M L A

SPECIAL INVITEE

- ***** Shri Tek Chand Sharma, MLA

SECRETARIAT

1. Shri R.K. Nandal, Secretary
2. Shri Naren Dutt, Deputy Secretary

The Subject Committee was constituted vide Haryana Vidhan Sabha Secretariat, Notification No. HVS/F&C-1/2016-17/27, dated 25th April, 2016.

-
- * Shri Vipul Goel, MLA resigned from the Chairmanship of the Committee w.e.f 22nd July, 2016 A.N. on being appointed as Cabinet Minister of Haryana
- ** Dr. Pawan Saini, MLA was appointed as Chairperson w e f 26th July, 2016 for the remaining period of the year, 2016-17
- *** Nominated as Shri Tek Chand Sharma, Special Invitee of the Committee by the Hon'ble Speaker w.e.f 11th May, 2016 for the remaining period of the year 2016-2017
- **** Nominated as Shri Mahipal Dhanda, as Member of the Committee by the Hon'ble Speaker w.e.f 1st June, 2016 for the remaining period of the year 2016-2017
- ***** Nominated as Shri Bikram Singh Yadav, as Member of the Committee by the Hon'ble Speaker w.e.f 9th August, 2016 for the remaining period of the year 2016-2017

(v)

INTRODUCTION

1. I, the Chairperson of the Subject Committee on Food & Supplies having been authorized by the Committee to present the Report on their Behalf, present this Second Report to the House
2. The matters covered by this Report were finally considered by the Committee at their sitting held on 27th February, 2017 and adopted this Report
3. A brief record of the proceedings of each meeting of the Committee has been kept on record of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.
4. The Committee is thankful to the representatives of the Food & Supplies Department who appeared before the Committee from time to time for their valuable assistance to the Committee
5. The Committee is also highly thankful and appreciates the working of the Secretary, Deputy Secretary, Branch officials of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their unstinted, whole-hearted co-operation and assistance rendered by them.

Chandigarh
The 27th February, 2017

Dr Pawan Saini
Chairperson

REPORT

- 1 The Subject Committee on Food & Supplies for the year 2016-2017 consisting of Chairperson/Members was nominated by the Hon'ble Speaker, Haryana Vidhan Sabha under Rule 276 of the Rules of Procedure and conduct of Business in Haryana Legislative Assembly on the 25th April, 2016
2. Dr Pawan Saini, MLA was appointed as the Chairperson w e.f 26th July, 2016 for the remaining period of the year 2016-17 of the Subject Committee by the Hon'ble Speaker
- 3 The Committee held **60** meetings (at Chandigarh and outside Chandigarh) till the finalization of this Report

FUNCTIONS OF THE COMMITTEE

The scope and functions of the Committee are set down in Rules 277 of the Rules of Procedure and conduct of Business in Haryana Legislative Assembly

The function of Committee are as under:-

- (i) to Scrutinize the demands for grants,
- (ii) to examine the working of these Departments and to suggest measures for improvement in administration and in different programmes/ schemes/ projects,
- (iii) to examine legislation,
- (iv) to advise Government on a question of policy or legislation on which Government may consult a committee
- (v) to discuss generally and formulate views on -
 - (a) State's Five Year Plan programmes relating to these Department and their implementation,
 - (b) Reports of any statutory or other body, including any Commission of Inquiry, which are laid before the House relating to these Departments; and
 - (c) Annual Performance Reports of the Department

The Subject Committee shall not examine or investigate matters of day-to-day administration

FOOD & SUPPLIES DEPARTMENT

Committee prepared the following questionnaire

- 1 Discussion with the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Food & Supplies Department, Chandigarh regarding new schemes, ongoing schemes and details of budget allocation under various schemes of Food & Supplies Department for the year 2016-17.
- 2 विभाग द्वारा बी०पी०एल० सर्वे कब किया गया था और उस समय कितने बी०पी०एल० कार्ड होल्डर थे और कितने परिवार बी०पी०एल० से लाभान्वित हुए? बी०पी०एल० परिवारों को क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं? और क्या विभाग द्वारा बी०पी०एल० का री-सर्वे करने का कोई विचार है या नहीं? और बी०पी०एल० का क्या क्राइटेरिया है?
- 3 क्या बी०पी०एल० कार्ड धारकों का आधार नम्बर से लिंक किया गया है? अगर किया गया है तो 30 मई तक कार्ड धारकों की नम्बर आफ क्वांटिटी क्या है? जो लाभार्थी उनको कब तक आधार नम्बर से जोड़ दिया जाएगा?
- 4 हरियाणा के अन्दर डिपूहोल्डरस को राशन डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए विभाग से क्या-क्या सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में दी जाती है? क्या राशन डिपू लेने के लिए एक आदमी एक से अधिक राशन डिपू ले सकता है? वर्ष 2015-16 में राशन डिपू की कितनी बार जांच की गई है? निरीक्षण जांच रिपोर्ट कमेटी को उपलब्ध कराई जाए।
- 5 क्या विभाग के पास भण्डारण करने के लिए कवर्ड गोदाम हैं अगर हैं तो उनकी क्षमता कितनी है और गोदाम का कितना कवर्ड एरिया किराये पर लिया गया है और किस रेट पर लिया जाता है तथा प्रदेश में कितने साईलोज हैं उनकी स्टोरेज क्षमता कितनी है तथा नये साईलोज लगाने का क्या कोई प्रस्ताव है?
- 6 वित्तीय वर्ष 2015-16, के दौरान विभाग द्वारा कितने पेट्रोल पम्पों तथा एल०पी०जी० गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया गया। समिति को सम्पूर्ण रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाए और कितने दोषी पाये गये?
- 7 वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 के दौरान खाद्यानों, कम नापतोल तथा उच्च दरों इत्यादि में परिवर्तन के विरुद्ध डिपोधारकों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थी तथा प्राप्त शिकायतों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?
- 8 अतिरिक्त पहुँच को समायोजित करने के लिए स्थानों का निर्धारण तथा पहुँच को समायोजित करने के लिए मण्डियों में कम स्थान तथा बारदाने की समस्या सुलझाने में विभाग द्वारा क्या पग उठाये गये?

- 9 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग द्वारा कितनी उचित मूल्य दुकानों की जांच की गई थी। समिति को सम्पूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाए?
उचित मूल्य दुकान के लाईसैंस जारी करने के लिए विभाग द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है?
- 10 पी0डी0एस0 सिस्टम में सुधार के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
- 11 क्या विभाग द्वारा राशन कार्ड होल्डरस की जांच की गई है यदि हां तो कमेटी को अवगत कराया जाए कि जांच के दौरान कितने राशन कार्ड अवैध पाए गए हैं तथा उन अवैध राशन कार्ड होल्डरस के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही की गई है? उसका जिलावार पूरा ब्यौरा कमेटी को दिया जाए तथा नए राशन कार्ड कब तक बनाए जाएंगे?
- 12 खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की जिलावार संख्या उनके पद अनुसार कमेटी को बताई जाये। ऐसे कितने अधिकारी /कर्मचारी हैं जो अनौपाचारिक रूप से एडोहक या बाहरी स्रोत से सेवा प्राप्त कर विभाग में कार्यरत हैं। उनकी भी जिलावार पूरा विवरण पद अनुसार कमेटी को भिजवाया जाये?
- 13 जो 9.50 लाख मीट्रिक टन साईलोज बनाने का प्रस्ताव है क्या उसके लिए आवेदन मांगे गए हैं या नहीं ? यदि हां तो किस-किस कंपनी के आवेदन प्राप्त हुए हैं उनकी सूची नियम एवं शर्तों के अनुसार पूरा विवरण कमेटी को भिजवाया जाए ?
- 14 प्रधान मंत्री उज्वला योजना के अनुसार हरियाणा प्रदेश के बी.पी.एल. परिवारों को कितने गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए गए हैं और कितने ऐसे कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है?
- 15 पेट्रोल एवं डीजल की वितरण प्रणाली के क्या मापदंड हैं और इनके स्टॉक की क्या प्रतिबद्धता है? इसका पूरा विवरण कमेटी को भिजवाया जाए?
- 16 क्या एल.पी.जी. गैस एजेंसिज की क्षमता निर्धारित की गई है? किसी भी गैस एजेंसी में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने कनेक्शन बांटने की क्षमता है और एल.पी.जी. गैस वितरण की क्या प्रणाली है? प्रदेश में कुल कितने गैस उपभोक्ता हैं और ऐसे कितने उपभोक्ता हैं जिन्होंने अपनी गैस सब्सिडी स्वतः छोड़ रखी है इसका जिलावार पूरा विवरण कमेटी को दिया जाए?
- 17 जिलावार कितना खाद्यान खुले में रखा गया है और कितना खाद्यान कवर्ड एरिया में रखा गया है। जो खाद्यान खुले में रखा गया है उसको नुकसान से रोकने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं इसकी भी जिलावार जानकारी कमेटी को

दी जाए। जो खाद्यान खुले मे रखा गया है उसका अब तक कितना नुकसान हुआ है इसकी भी जिलावार जानकारी कमेटी को दी जाए। क्या दो साल से पुराना खाद्यान स्टॉक में है यदि हां तो इसकी भी जिलावार जानकारी कमेटी को दी जाए?

- 18 वर्ष 2014 तक प्रदेश में कितने बी०पी०एल० कार्ड धारक थे तथा आज तक कितने बी०पी०एल० कार्ड धारकों की कटीती/ बढोतरी की गई है, इसकी पूरी जानकारी जिलावार कमेटी को उपलब्ध करवाई जाए?
- 19 जो खाद्य सामग्री विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को वितरित की जाती है उस खादय सामग्री की क्वालिटी चैक करने के क्या मापदण्ड/कसौटी है?
- 20 भट्टों के लाईसैंस प्रदेश में विभाग द्वारा दिए जाते हैं। उसमें ईटों का आकार, वजन, कीमत और ईटों की गुणवता निर्धारित करने के क्या मापदण्ड हैं। इसकी पूरी सूचना पूरे विवरण के साथ कमेटी को दी जाए

FOOD & SUPPLIES DEPARTMENT, HARYANA

Answer No.1

Procurement of Wheat/Paddy, Storage capacity and Delivery of CMR. Procurement

Government of India announces Minimum Support Prices of wheat and paddy every year to ensure that farmers get the remunerative prices of their produce and they do not resort to distress sale. To implement the MSP scheme of Government of India five procurement agencies namely Food Department, Hafed, HAIC, HWC and Food Corporation of India (the central agency) make purchases of wheat/Paddy in the mandis allotted to them as per their procurement share i.e. Food Department 33%, Hafed 33%, HAIC 10%, HWC 12% and FCI 12%. The period of procurement of wheat is fixed every year by Government of India on the request of State Government. For Rabi Marketing Season 2016-17 the period of procurement is from 1st of April to 15th of May. The period of procurement of paddy generally remains from 1st of October to 15th of December every year but this year due to early arrival of paddy Government of India preponed the paddy procurement season from 1st October to 24th September on the request of State Government.

a) Wheat Procurement

The arrival and procurement of wheat during last 5 years remains as under -

Sr No	Year	Arrival (In LMT)	Procurement (In LMT)	Minimum Support Price (Rs Per qtl.)
1.	2012-13	87.30	87.16	1285
2.	2013-14	58.82	58.56	1350
3.	2014-15	65.11	65.07	1400
4.	2015-16	67.71	67.70	1450
5.	2016-17	65.16	65.14	1525

b) Paddy Procurement

The arrival and procurement of paddy during last 5 years remains as under -

Sr. No.	Year	Arrival (In LMT)	Procurement (In LMT)	Minimum Support Price (Rs Per qtl.)
1	2011-12	30.42	29.66	1110
2.	2012-13	40.05	38.53	1280
3	2013-14	36.71	35.87	1345
4	2014-15	30.21	30.07	1400
5	2015-16	45.28	42.59	1450

c) CMR Delivery from out of Paddy Procured

i. All Procurement Agencies:

Status of CMR delivery and balance during last 5 years

Sr No	Year	Paddy procured (Fig in L M T.)	CMR due (Fig. in L.M.T)	CMR delivered (Fig. in L M T.)	%age delivery	CMR balance
1	2011-12	18 46	19 87	19 71	99 19	0 16
2	2012-13	24 16	25 81	25 79	99 92	0 02
3.	2013-14	14.62	24.03	23.42	97.46	0 61
4.	2014-15	18 11	20 14	19 86	69 61	0 28
5	2015-16	20 14	28 58	26.79 (current season)	93.73	1.79

ii. Food & Supplies Department

Position of Delivery of CMR and Balance during last 5 years.

Sr No.	Year	Paddy procured (Fig. in L M.T.)	CMR due (Fig in L M.T.)	CMR delivered (Fig in L M T)	%age delivery	CMR balance
1	2011-12	10 72	7 18	7 18	100	-
2	2012-13	14.70	9.84	9 83	100	945 MT
3	2013-14	14 49	9 70	9 23	95 15	0 47
4	2014-15	12 78	8 56	8 35	97 54	0.21
5	2015-16	19 44	13 02	12 05 (upto 30 04.2016)	92 54	0 97

2. Storage Capacity & Construction of Godowns

(i) Storage Capacity:-

The State of Haryana has the following Storage Capacity for the safe storage of food grains -

Food Department	=	03 57 LMT
Hafed	=	11 71 LMT
HSWC	=	14 73 LMT
HAIC	=	01 01 LMT
FCI	=	07 58 LMT
CWC	=	04 96 LMT
HSAMB	=	04.03 LMT
PEG	=	34 02 LMT
Adani Silos	=	02 00 L MT
Total	=	83.61 LMT

(ii) **Constructions of Godowns:-**

In this regard it is informed that three projects of construction of godowns at Bhor Sainda (Kurukshetra) for the capacity of 26442 MT, Kharkhoda (Sonapat) for the capacity of 44814 MT and Tigaon (Faridabad) for the capacity of 21098 MT total capacities 89678 MT are being undertaken with the Assistance of NABARD. The total estimated cost of these projects is Rs 4661.80 lac. Out of this, NABARD has sanctioned a loan of Rs 4428.72 lakh and Rs 233 08 (5% of total cost) is to be borne by the State Government. As per information received from the Hafed and HSWC about 45 to 70% construction work of godown has been completed so far. The projects are likely to be completed by 31 03.2017. Budget provision for this has been made for Rs 20.00 Crore

The detail of the loan and its utilization is as under:-

Name of the NABARD funded scheme	Approved Outlay (Rs)	NABARD (Rs)	Budget provision for the FY 2015-16 including RE (Rs.)	Fund released by the NABARD (Rs.) up to 30.09.2015	Fund released/ expenditure by FD (Rs)	Balance from NABARD (Rs)	Progress of work
Warehousing Infrastructure Fund (WIF) Bhor Sainda (Kurukshetra), Kharkhoda (Sonapat) and Tigaon (Faridabad)	46,61,80,000	44,28,72,000	30,00,00,000	8,85,74,000 (as 20% mobilization advance)	5,00,00,000 (on 04 06 2015), 4,85,00,000 (on 02 09 2015) and	35,42,98,000	45-70%
2 nd Installement				5,74,31,000	5,75,00,000 (on 03 12 2015)	- 5,74,31,000	
3 rd Installement				10,57,77,000	4,40,00,000 dt 26 02.2016	- 10,57,77,000	
TOTAL	46,61,80,000	44,28,72,000	30,00,00,000	25,17,82,000	20,00,00,000	19,10,90,000	

Other than above Hafed is constructing godown for a capacity of 102861 MT, HSWC for 47070 MT and HAIC for 32786 MT. The State has been allotted a capacity of 9 5 LMT for Silos which will be completed by the year 2020. Out of this 4.5 LMT capacity will be constructed by State and its procurement agencies and rest by F C I

3. TARGETED PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM (TPDS) UNDER NFSA

Haryana is implementing Targeted Public Distribution System (TPDS) with focus on Below Poverty Line (BPL) and Antyodaya Anna Yojana (AAY) families. Identification of these families is done by Rural Development and Urban Local Bodies Departments Haryana, in rural and urban areas respectively. BPL census is conducted in the State as per procedure/ parameters/guidelines prescribed by Government of India by these

Departments in their respective areas. Utmost care is taken in identification of these families with emphasis on transparency and genuineness. Once identified, Department of Food & Supplies issues pink colour ration cards to AAY and yellow colour ration cards to BPL families. In addition, green colour ration card is issued to all those families who do not figure in AAY or BPL categories. These families are generally referred to as APL (Above Poverty Line) families

The BPL and AAY families already identified by these Departments are automatically covered under NFSA, 2013. The criteria for OPH beneficiaries i.e. families having upto 2 acre of land holding in rural area and 100 sq yard plot/flat in urban area are only treated as OPH. Families having more than rupees one lac annual income and having tractor or any other four wheelers are also excluded from the beneficiaries list. As per the criteria fixed by the State Government 132.56 lac are covered which are 6 lac excess then the limit fixed by GOI.

Monthly entitlement and prices of foodgrains distributed to beneficiaries are as under.-

Commodity	Allocation in MTs/KLs	Category	Scale in kg/Ltr per card per month	Consumer end Price Rs. per kg./Litre
Wheat	66250 MT (per month)	Priority Household (SBPL+CBPL+OPH)	5 kg per unit	2.00
		AAY	35	2.00
Sugar	2485 MT (per month)	BPL including AAY	2	13.50
Kerosene	4104 KL (per month)	BPL including AAY	7	14.03 to 14.70 (Depending upon the transportation)
Pulses	6844 MT (October to December, 2015)	BPL including AAY	2.5	20.00

Allocation of above commodities is being issued on the basis of digitized/verified figures since June, 2015

Ration Cards details :

Category	Ration Cards	Units
AAY	255974	1103746
CBPL	453596	2131293
SBPL	396815	1804959
OPH	1833225	8211591
TOTAL	2939610	13251589

Targeted Public Distribution System was started on May, 1997 in the State. However, from 20th August, 2013 the National Food Security Act, 2013 has been implemented in the State. With the implementation of this Act, the number of beneficiaries under Targeted Public Distribution System has increased from 54 41 lac to 126 49 lac of this rural.urban share is as under -

Population in lac (2011)			Coverage of population under National Food Security Act, 2013		
Rural	Urban	Total	Rural	Urban	Total
165.315	88.216	253.531	90.28 lac (54.61%)	36.21 lac (41.05%)	126.49 lac (49.89%)

The Department of Food and Supplies has a comprehensive structure at the district, block and grassroots level. It has a chain of District Food and Supplies Controllers (DFSCs), District Food and Supplies Officers (DFSOs), Assistant Food and Supplies Officers (AFSOs), Inspectors Food and Supplies (IFSs) and Sub-Inspectors Food and Supplies (SIFSs) who facilitate the lifting and distribution of foodgrains and other essential commodities as per the allocations made by the Government. Confed acts as wholesale nominee in the distribution of essential commodities other than kerosene oil. Oil companies appoint wholesale dealers for kerosene oil. Food and Supplies Department has setup a network of 9307 Fair Price Shops, 2856 in urban and 6512 in rural areas of 21 districts of the state.

The Government is committed to improve the system so that shortcomings are removed and benefits reach the needy and genuine beneficiaries. In this regard, Village/Ward level Vigilance Committees have been constituted to keep a watchful eye on the distribution of essential commodities and are empowered to monitor actual distribution. In addition, Gram Panchayats, Panchayat Samities and Zila Parishad are also involved in distribution and monitoring of PDS.

4. DAL ROTI SCHEME

Along with National Food Security Act, 2013, the State Government also launched Dal Roti Scheme on August 20, 2013. Under this scheme the State Government is providing 2.5 kg of pulses per month at subsidized rate of Rs 20 per kg to AAY and Below Poverty Line (BPL) families, so as to meet their nutritional and proteins needs. The scheme caters to the need of 11.06 lac families. The scheme is being run exclusively with State subsidy, Rs 160 crore annually under the Plan Scheme. It has been observed that there is a steep rise in the prices of pulses since last 2-3 months which incurred an expenditure of Rs.45 crore (approx) for the distribution of pulses. State Government has decided to distribute pulses (Chana Dal) for the month of January to June, 2016 in one go i.e. 15 kg per family and distribution of pulses will be completed by the end of May, 2016.

5. End-to-End Computerization of TPDS/NFSA Operations

Background

Administrative approval of Government of India for implementation of the Component-I of the Plan Scheme on End-to-End Computerization of TPDS operations in all States/UTs under the 12th Five Year Plan (2012-17) has been received vide letter No.23(6)/2008-PD-2-Comp Vol V dated 10 12 2012 during the period 2012-17 on 50:50 cost sharing between Centre and State

Targeted Public Distribution System (TPDS) is aim at ensuring Food Security of the people, especially the poor and vulnerable sections. Evaluation studies have pointed out certain shortcomings in its implementation, such as leakages and diversion of foodgrains, inclusion and exclusion errors in identification of beneficiaries, etc. Government has taken measures to address these shortcomings but it is felt that computerization of TPDS will be an important step to bring transparency to the system

Objective

TPDS encompasses the process of allocation of foodgrains, storage, beneficiaries identification and management of delivery of foodgrains to beneficiaries. There are multiple stakeholders involved at various levels in operations of TPDS, namely Central Government, State Government/UT Administration, Food Corporation of India (FCI), State Civil Supplies Corporations, other agencies at State level, FPS dealers, beneficiaries, etc. For better coordination among various agencies for ensuring timely delivery of foodgrains at FPS level, it is necessary that information regarding movement of foodgrains is available on a common platform. Huge difference between cost of the foodgrains and CIPs creates incentives for leakages and diversions. With computerization of supply-chain, the movement of foodgrains upto FPS level cannot be tracked and the problem of leakage and diversion can be addressed. Digitization of beneficiaries database will help in weeding out the bogus ration cards and better targeting of subsidies. Facilities of SMSs, e-mails, Toll Free Numbers will be used to inform the beneficiaries about the availability of TPDS supplies in the FPS, which will ensure timely and transparent distribution of foodgrains to beneficiaries as per their entitlement. Transparency portal and social audit will further strengthen the functioning of FPSs and ensure accountability at various levels. Beneficiaries will also be able to register their grievances through toll free numbers and seek its resolution.

The key components of the scheme on End-to-End computerization of TPDS operations and their respective expected outcomes are briefly described as below.-

- 1 Digitization of beneficiaries and other databases
- 2 Computerization of Supply Chain Management
- 3 Setting up of Transparency portal and Grievance Redressal mechanisms

Component wise status of the project in the State since November, 2014 is as under:-

Component wise status of the Project in the State since November 2014 is as follows:

1. **Component-I:**

A) Digitization of beneficiary and other databases: 29,40,457 families (AAY {Antodya Anna Yojana}, CBPL {Central Below Poverty Line}, SBPL {State Below Poverty Line} and OPH {Other Priority Household}) having 1,32,55,267 beneficiaries have been digitized and verified 25,36,137 (86.25%) Ration Cards have Aadhaar number of at least 1 member and 94,33,732(71.2%) beneficiaries' Aadhaar have been seeded. The process of seeding of Aadhaar of remaining beneficiaries in PDS database is in progress.

- i **Digitization of FPS Data:** Master data entry of 9476FPS has been completed and ported to ePDS {electronic Public Distribution System} module of CAS (Common Application Software).
- ii. **Digitization of Godowns and Agencies Data:** Master data entry of 479 godowns has been completed and ported to FEAST (Food & Essential Commodities Assurance and Security Target) module of CAS.

B) Computerization of Supply Chain Management: The Department is implementing Food & Essential Commodities Assurance & Security Target (FEAST) Software for online allocation and supply chain management FEAST for Online has been tested. Trial Online allocation has been started from January 2016 Supply Chain Management is likely to be implemented from June 2016 **Training of Departmental Staff (AFSO/IFS/SIFS and Dealing Assistant) regarding ePDS and FEAST** was conducted from 04th January to 09 January, 2016 at Divisional Level Refresher training would be held in the month of June, 2016 Common application Software (CAS) for PDS has been installed at National cloud (Meghraj) and hardware at State HQs and District HQs has also been installed Computer hardware for 146 Ration Card Preparation Centers, Godowns and DM, Confed offices under installation and installed by May, 2016

C) Setting up of Transparency Portal and Grievances Redressal Mechanisms: Transparency Portal of the Department (**Error! Hyperlink reference not valid.**) is functional and is being updated regularly Toll Free PDS helpline number 1967 and 1800-180-2087 are operational The online grievances redressal system developed by NIC exclusively for PDS complaints is under testing in Panchkula district The PDS related complaints received on CM Window are disposed of expeditiously So far 2965 complaints have been up to 25 4 2016 out of which 2520 (85%) complaints disposed off/action taken

2. **Component-II (FPS Automation).**

The State has finalized the system Integrator (Private Agency) models for FPS automation. Process regarding appointment of System Integrator for

implementation of FPS automation has been initiated and is likely to be completed shortly and FPS automation is likely to be implemented in entire State by December, 2016

NEW SCHEMES OF THE DEPARTMENT

1 E-Procurement and direct payment to farmers (New Scheme)

Under this project, the farmer wise procurement will be captured on real time basis in the mandi premises. All the transactions made in mandi will automatically be uploaded in the web-server through e-procurement- web-portal. This software will provide farmer wise detail of procurement to the department and procurement agencies. The payments will be made through RTGS directly to the farmers as per option given by them. The system will send the SMS alert to the farmers regarding their payments. The system will also be helpful in sending the data to GOI in different module of FCI Depot Online System. End-to-End Computerisation of PDS will also be facilitated through this application for on-line allocation and lifting of food grains from the warehouses. E-Procurement of foodgrains under MSP and optional direct payments to the farmers will be launched on pilot basis from coming Kharif Marketing Season, 2016 i.e. 1st October, 2016.

2 Printing of new Ration Cards

Ration Cards were printed long back in 2005 which are in a very poor condition. It is necessary to replace these ration cards with new ration cards. At present there are 29,39,610 beneficiaries ration cards and 1,32,51,589 units under TPDS scheme of NFSA, 2013. As per mandate 255974 ration cards of AAY families, 850411 ration cards of CBPL and SBPL families and 1833225 Ration cards of OPH (Other Priority Household) families will be printed and distributed to the beneficiaries. The Ration Card will carry the logo of Golden Jubilee Year. The department has invited tenders for printing of new ration cards through security printing press. The technical bid would be opened on 06.05.2016.

**Detail of Budget allocation under various schemes of
Food & Supplies Department for the year 2016-17.**

(Fig. in lacs)

Major Head "2408-Food Storage & Warehousing" (Plan)	
Scheme	Amount Sanctioned
(91) End to End Computerization	800.00
(93) Dal Roti Scheme	16000.00
Total Plan Budget (2408)	16800.00
Major Head "2408-Food Storage & Warehousing (Non-Plan)	
(94) Public Distribution System (Smart Card)	1250 00
(96) District Fora	1766 00
(97) State Commission	269.00
(98) Field Staff	14694 00
(98) Field Staff (Charged)	40 00
(99) Directorate	1140 30
Total Non-Plan (Budget)	19159.30
Major Head "3456-Civil Supplies" (Non-Plan) (Jago Grahak Jao)	
(104) Consumer Welfare Fund	421 49
Major Head "3475-Other General Economics Service"	
(106) Regulation of Weight & Measures	478.33

(Fig. in Crore)

Major Head "4408-Capital Outlay" (Non-Plan)	
Scheme	Amount Sanctioned
(50) Advance Grain Supply	9236.51
(25) Interest	400 00
(16) Major Works (Godown)	30 00
Total Non-Plan Budget (4408)	9666.51

Major Head "4408-Capital Outlay" (Plan)	
Scheme	Amount Sanctioned
(16) Major Work (Godown)	20 00

Major Head "6003-C C.L." (Charged)	
Scheme	Amount Sanctioned
	6500.00

उत्तर 2

विभाग द्वारा बीपीएल सर्वे नहीं किया जाता है। बीपीएल परिवारों के सर्वे का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास तथा शहरी क्षेत्र में शहरी निकाय विभाग द्वारा किया जाता है। सर्वे के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड भी उक्त दोनों विभागों द्वारा ही अपनाए जाते हैं। ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर उपलब्ध करवाई गई सूचि अनुसार खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा लाभार्थियों को बीपीएल तथा एएवाई के राशन कार्ड जारी करने है। राज्य के सभी अतिरिक्त उपायुक्तों को जिला में बीपीएल सर्वे का नोडल अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय द्वारा बीपीएल सूचि में जो परिवर्तन किया जाता है उसे जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक तदानुसार अपने रिकार्ड में भी परिवर्तन करता है। वर्तमान में हरियाणा राज्य में कुल 11,06,897 परिवारों को बीपीएल/एएवाई की श्रेणी में रखा हुआ है जिन्हे विभाग द्वारा दो रूप्ये प्रति किलो खाद्यान्न के अतिरिक्त 2 किलो चीनी, 2.5 किलो दाल तथा 7 लिटर मिट्टी तेल प्रति परिवार दिया जाता है परन्तु उन (520474 बीपीएल/एएवाई) परिवारों को तेल नहीं दिया जाता, जिन परिवारों के पास एलपीजी गैस कनेक्शन है। वर्तमान में विभाग द्वारा BPL Survey करना विचाराधीन नहीं है। बीपीएल/एएवाई का सर्वे शहरी/ग्रामीण विकास विभाग हरियाणा द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर करवाया जाता है।

उत्तर 3

जी हां, बीपीएल कार्ड धारकों को आधार नम्बर से लिंक किया गया है। 30 मई, 2016 तक 11,05,911 बीपीएल/एएवाई कार्डधारकों में से 10,00,029 बीपीएल/एएवाई कार्डधारकों को आधार कार्ड से लिंक किया जा चुका है शेष बीपीएल/एएवाई कार्डधारकों को भी नवम्बर, 2016 तक आधार कार्ड से लिंक करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त विभाग में NFSA के तहत 18,31,634 अन्य प्राथमिक परिवार (PH) कार्ड धारकों में से 15,67,091 को भी आधार कार्ड से लिंक किया जा चुका है शेष बचे अन्य प्राथमिक परिवार कार्ड धारकों को भी नवम्बर 2016 तक आधार कार्ड से लिंक करने का प्रयास किया जा रहा है।

उत्तर 4

i. Scale and issue price of PDS items under NFSA, 2013: -

Category	Wheat @ Rs 2 per Kg	Kerosene Oil @ Rs 14.03 to 14 70 per ltr	Sugar @ Rs 13 per Kg	Dal @ Rs 20 per Kg
AAY	35 Kg per card	7 ltr	2 Kg per family	2.5 Kg per family
CBPL/SBPL	5 Kg per unit	7 ltr.	2 Kg per family	2.5 Kg per family
Pnonty Households	5 Kg per unit	-	-	-

ii PDS Contorl Order-2009 के अनुच्छेद 4.(3) के तहत उचित कीमत की दुकान के स्वामी के परिवार का कोई भी सदस्य अन्य उचित कीमत की दुकान के लिए दुसरी अनुज्ञापति प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा तथा न ही किसी दुसरे के नाम से (बेनामी) अनुज्ञापति के अधीन कोई कारोबार कर सकता है।

व्याख्या-“परिवार” में वे सभी व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम उचित कीमत की दुकान के स्वामी के राशन कार्ड में दर्ज किए हुए हैं या जो उस पर आश्रित हैं।

iii. वर्ष 2015-16 में राशन डिपू की 6090 बार जांच की गई है। सम्पूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट निम्न प्रकार से है:-

Monthly Action Taken Report 2015-16	
Subject	Total
No. of Inspection	6,090
No. of raid conduct	124
No of person arrest	6
No of person prosecuted	5
No. of person convicted	5
No. of FPS licence suspended	884
No. of FPS licence cancelled	222
No. of FPS show cause notice issued	1,571
Value of goods seized (in rupees)	40,012
Amount of Security forfeited (Rs)	22,81,010

iv. मुख्यालय के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। हां इतना आवश्यक है कि समय-2 पर विभाग में एक व्यक्ति द्वारा किसी दुसरे व्यक्ति के नाम से डिपू चलाने की शिकायतें प्राप्त होती हैं जिन पर जांच उपरांत उचित कार्यवाही की जाती है। हरियाणा राज्य में जिलावार डिपोहोल्डर्स की सूची निम्न प्रकार से है:-

Name of the Districts	Total No. of FPS as on 30.04.2016		
	Urban	Rural	Total
Ambala	113	270	383
Bhiwani	141	517	658
Faridabad	605	145	750
Fatehabad	65	279	344
Gurgaon	84	139	223
Hisar	207	513	720
Jhajjar	61	246	307
Jind	141	426	567
Kaithal	92	371	463
Karnal	196	410	606
Kurukshetra	86	324	410
Mewat	22	323	345
Narnaul	34	248	282
Palwal	87	302	389
Panchkula	51	102	153
Panipat	148	315	463
Rewari	61	235	296
Rohtak	109	182	291
Sirsa	201	412	613
Sonipat	108	312	420
Yamuna Nagar	178	417	595
Total	2790	6488	9278

उत्तर 5

विभाग के पास कवर्ड भण्डारण के लिये 3.78 लाख मीट्रिक टन क्षमता के कवर्ड गोदाम है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा 68,580 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जा रहा है जोकि 31.03.2017 तक पूर्ण हो जाएंगे। विभाग द्वारा हरियाणा राज्य मार्किटिंग बोर्ड के 1.58 लाख मीट्रिक टन क्षमता के कवर्ड गोदामों को सात वर्षीय गारंटी स्कीम के तहत 9/- रु0 प्रति टन, प्रति मास की दर से लिया गया है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पडने पर प्राईवेट गोदामों को भी इसी दर पर किराये पर ले लिया जाता है। इस समय हरियाणा राज्य में अडानी ग्रुप के ढाण्ड जिला-कैथल में दो लाख मीट्रिक टन क्षमता के साईलोज है जिनको भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराये पर लिया हुआ है। हरियाणा राज्य में भारत सरकार ने वर्ष, 2019-20 तक तीन चरणों में 9.50 लाख मीट्रिक टन क्षमता के साईलोज बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रथम चरण में 3 लाख मीट्रिक टन, द्वितीय चरण में 2 लाख मीट्रिक टन तथा तृतीय चरण में 4.5 लाख मीट्रिक टन क्षमता के साईलोज पी0पी0पी0 मोड पर बनाए जाने है। प्रथम व द्वितीय चरण के साईलोज भारतीय खाद्य निगम तथा तृतीय चरण के साईलोज राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने है। इस सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम द्वारा साईलोज बनाने के लिये स्टोरेज गैप तैयार किया जा रहा है। इस समय हरियाणा राज्य की कुल कवर्ड भण्डारण क्षमता 89.48 लाख मीट्रिक टन है।

उत्तर 6

पेट्रोल पम्पों की संख्या	चैकिंग (पेट्रोल/डीजल)	टिप्पणी
2385	2534	वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 2385 पेट्रोल पम्पों में से 2534 (1325 पेट्रोल व 1209 डीजल) के सैम्पल Density Check करने के लिए डा किये गये। इन सैम्पलों के विरुद्ध कोई भी सैम्पल फेल नहीं हुआ और जहां तक Petrol Pump द्वारा Short delivery की शिकायतों का संबंध है, के विषय में वर्णित किया जाता है कि इस बारे निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान द्वारा इस अवधि में Petrol Pumps की जांच के समय 24 पेट्रोल पम्पों में अनियमितताएँ पाने के कारण उनके विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत उनका चालान किया गया और सहायक नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान द्वारा बतौर जुर्माना 2,33,000/-रु0 कम्पाउंडिंग फिस वसूल किए गए।
गैस एजेंसी की संख्या	वर्ष 2015 - 2016 के दौरान की गई चैकिंग	टिप्पणी
418	485	11 गैस एजेंसियां Defaulter पाई गईं जिनमें से 10 गैस एजेंसियों को चेतावनी जारी की गई है तथा कैथल जिले की एक गैस एजेंसी जिस

द्वारा ग्राहको से ठीक व्यवहार/समय पर गैस की डिलीवरी ने करने के कारण उसके विरुद्ध कार्यावाही करने हेतू सम्बन्धित ऑयल कम्पनी को लिखा गया। Defaulter एजैन्सीयों को मुख्यतयः सत्यापित स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक व रेट न भरे होना तथा गैस से भरे हुए/खाली cylinder की सख्यां में अन्तर होने के कारण चेतावनी जारी की गई।

उत्तर 7

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान खाद्यानों, कम नापतोल तथा उच्च दरों इत्यादि में परिवर्तन के विरुद्ध कुल 316 शिकायतें प्राप्त हुई थी तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 380 शिकायतें प्राप्त हुई। इन शिकायतों पर जांच उपरांत पी0डी0एस0 कन्ट्रोल ऑर्डर 2009 के नियमानुसार कार्यवाही की गई है, जैसे कि चेतावनी जारी करना, प्रतिभूति जब्त करना, प्रतिभूति जब्त करके डिपू रद्द करना तथा एफ0आई0आ0 दर्ज करवाना।

उत्तर 8

यह प्रश्न हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से सम्बन्धित है क्योंकि मण्डियों का विस्तार मार्किटिंग बोर्ड द्वारा किया जाता है फिर भी विभाग इस समस्या के समाधान के लिए उठान पर ध्यान देता है ताकि मण्डियों में पर्याप्त स्थान रहें। खरीद सीजन के दौरान मण्डियों में किसानों की आने वाली उपज को खरीद उपरान्त भारतीय खाद्य निगम को सीधा प्रेषण के अतिरिक्त अपने गोदामों में भी भण्डारित करवाया जाता है ताकि प्रतिदिन किसानों की आने वाली नई उपज के लिए स्थान की कमी न रहे। इसके अतिरिक्त मण्डियों से पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध करवाया जाता है तथा गत वर्षों में खरीद के दौरान बारदाने की कोई कमी नहीं हुई है।

उत्तर 9

i. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग द्वारा 6090 उचित मूल्य दुकानों की जांच की गई थी। सम्पूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट निम्न प्रकार से है:-

Monthly Action Taken Report 2015-16	
Subject	Total
No. of Inspection	6,090
No. of raid conduct	124
No of person arrest	6
No. of person prosecuted	5
No of person convicted	5
No. of FPS licence suspended	884
No. of FPS licence cancelled	222
No. of FPS show cause notice issued	1,571
Value of goods seized (in rupees)	40,012
Amount of Security forfeited (Rs)	22,81,010

डिपोधारक की जाँच के लिए निर्धारित निरीक्षण प्रोफार्मा की प्रति संलग्न है।

ii. PDS Contorl Order-2009 के अनुच्छेद 5.(1) के तहत अनुज्ञापन प्राधिकारी उचित मूल्य की दुकान के लिए स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय प्रचार तथा मुनादी द्वारा प्रार्थना पत्र मांगेगा। यदि कोई आवेदक स्नातक है, तो उसे वरीयता दी जायेगी। सभी पात्र आवेदकों का वरीयता क्रम निम्न प्रकार से होगा:-

1. स्वयं सहायता समूह या साक्षर महिला समूह;
2. बेरोजगार महिला/ पुरुष स्नातक;
3. अनुसूचित जाति महिला/पुरुष;
4. पिछड़ा वर्ग (ए) महिला/पुरुष;
5. भूतपूर्व सैनिक;

ग्रामीण क्षेत्र में जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक, सम्बन्धित खाद्य एवं पूर्ति निरीक्षक तथा गांव का सरपंच तथा शहरी क्षेत्र में जिला खाद्य तथा पूर्ति नियन्त्रक, सम्बन्धित खाद्य एवं पूर्ति निरीक्षक तथा नगरपालिका पार्श्व की समिति उनकी प्राथमिकता/वरीयता अनुसार पात्र आवेदकों के नाम की सिफारिश अनुज्ञापन प्राधिकारी को करेगी । अनुज्ञापन प्राधिकारी अगले 7 दिन के अन्दर ऐसी सिफारिश किये गये आवेदक को उचित मूल्य की दुकान का स्वामी के रूप में नियुक्त करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेशों के जारी करने के पन्द्रह दिन के अन्दर अनुज्ञापन प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील उपायुक्त के समक्ष की जाएगी। उपायुक्त तीस दिन के भीतर अपील पर निर्णय करेगा । अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा ।

उत्तर 10

पी0डी0एस0 सिस्टम में सुधार के लिए विभाग द्वारा निम्न कदम उठाए जा रहे हैं :-

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंत से अंतिम तक कम्प्यूटीकरण विभाग द्वारा मास नवंबर, 2014 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन के कम्प्यूटीकरण के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 50-50 प्रतिशत के सहभाजन पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के अंत से अंतिम तक कम्प्यूटीकरण की योजना को लागू कर दिया गया है।

29,36,059 परिवारों (ए0ए0वाई, केन्द्रीय बी0पी0एल0, राज्य बी0पी0एल0 तथा अन्य प्राथमिक परिवार) का अंकुरण (digitized) तथा सत्यापन (verified) किया गया है। 25,70,116 (87.54%) राशन कार्ड में कम से कम एक सदस्य और 95,81,726 (72.4%) लाभार्थियों को आधार वरीयता दी गई है। 9,476 उचित मूल्य की दुकान और 479 गोदामों का मास्टर डाटा प्रविष्ट किया गया है। विभाग की पारदर्शिता (<http://haryanafood.gov.in>) पोर्टल कार्यात्मक है और इसे नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है। विभाग खाद्य एवं आवश्यक वस्तु आश्वासन और सुरक्षा (FEAST) सॉफ्टवेयर और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को ऑनलाईन एलोकेशन के लिए लागू कर

रहा है। विभागीय कर्मचारियों को ई-पी0डी0एस0 और खाद्य एवं आवश्यक वस्तु आश्वासन और सुरक्षा (FEAST) सॉफ्टवेयर के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जनवरी, 2016 से पूरे राज्य के लिए ऑनलाईन एलोकेशन का प्रशिक्षण किया जा रहा है और जून, 2016 से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।

टोलफ्री पी0डी0एस0 हेल्पलाईन नं0 1967 कार्य कर रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शिकायतों के लिए विशेष रूप से विकसित निवारण प्रणाली ऑन लाईन शिकायतों का परीक्षण किया जा रहा है और अनुकूलन के बाद जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

राज्य द्वारा उचित मूल्य दुकान के स्वचालन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर (निजी एजेंसी) मॉडल को अंतिम रूप दिया गया है। मास अक्टूबर 2015 से 20 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आधार आधारित बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही लाभार्थियों को वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। उचित मूल्य की दुकान के स्वचालन के कार्यान्वयन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और नवम्बर, 2016 तक इसे पूरे राज्य में लागू किए जाने की संभावना है।

2. निगरान कमेटी :- विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर नजर रखने के लिए डिपू स्तर पर निगरान कमेटी का गठन किया गया है जोकि उचित मूल्य की दुकान का स्वामी प्रत्येक मास उसे आबंटित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएँ उन पात्र उपभोक्ताओं को वितरित तथा अतिशेष स्टॉक इत्यादि की मात्रा की सूचना चौकसी समिति के किसी दो सदस्यों को देगा अन्यथा उचित कीमत की दुकान के स्वामी को अगले मास की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की आपूर्ति नहीं की जाएगी। वह चौकसी समिति के पूर्व मास में सभी आबंटित वस्तुओं के संतोषजनक वितरण बारे में "संतुष्टि प्रमाण पत्र" भी प्राप्त करेगा।

उत्तर 11

क्या विभाग द्वारा राशन कार्ड होल्डर्स की जांच की गई है यदि हां तो कमेटी को अवगत कराया जाए कि जांच के दौरान कितने राशन कार्ड अवैध पाए गए है तथा उन अवैध राशन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही की गई है? उसका जिलावार पूरा ब्यौरा कमेटी को दिया जाए तथा नए राशन कार्ड कब तक बनाए जाएंगे?

वर्तमान में विभाग द्वारा कार्ड होल्डर्स की कोई जांच नहीं की गई है। विभाग द्वारा नये राशन कार्ड बनाने बारे कार्यवाही पूर्ण करके यह मामला आपूर्ति एवं निपटान विभाग पंचकूला को हाई पावर परचेज कमेटी में रखने के लिए एजेण्डा भेजा हुआ है। राज्य में शीघ्र ही नये राशन कार्ड बनवाने बारे कार्यवाही शुरू हो जाने की सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त यहां यह वर्णन किया जाता है कि विभाग द्वारा मास नवंबर, 2014 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन के कम्प्यूटीकरण के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 50-50 प्रतिशत के सहभाजन पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के अंत से अंतिम तक कम्प्यूटीकरण की योजना को लागू कर दिया गया है। जिसके फलस्वरूप 29,37,545 परिवारों (ए०ए०वाई, केन्द्रीय बी०पी०एल०, राज्य बी०पी०एल० तथा अन्य प्राथमिक परिवार) का अंकुरण (digitized) तथा सत्यापन (verified) किया गया है। 25,67,120 (87.39%) राशन कार्ड में कम से कम एक सदस्य और 95,53,127 (72.1%) लाभार्थियों को आधार वरीयता दी गई है। आधार कार्ड नं० जो दोहराये जा रहे हैं NIC से 10 जून को प्राप्त की गई जिला अनुसार विवरणी इस प्रकार है:-

Sr No.	District Name	TOTAL			%age Duplicacy in RC
		Ration Card	Duplicate	Beneficiary	
1	AMBALA	149240	14825	57847	9.93%
2	BHIWANI	195814	11236	38871	5.74%
3	FARIDABAD	240266	58196	250040	24.22%
4	FATEHABAD	107818	9901	33858	9.18%
5	GURGAON	91777	11430	49703	12.45%
6	HISAR	226413	15695	60247	6.93%
7	JHAJJAR	89320	3476	13067	3.89%
8	JIND	172144	16479	66655	9.57%
9	KAITHAL	126754	4073	15117	3.21%
10	KARNAL	210795	23827	91540	11.30%
11	KURUKSHETRA	122129	8311	30263	6.81%
12	MAHENDRAGARH	91139	7047	26103	7.73%
13	MEWAT	145231	10462	58522	7.20%
14	PALWAL	108336	16941	89732	15.64%
15	PANCHKULA	48647	2414	9486	4.96%
16	PANIPAT	178589	30759	134848	17.22%
17	REWARI	88191	8734	34186	9.90%
18	ROHTAK	113718	5609	21623	4.93%
19	SIRSA	137551	9364	32893	6.81%
20	SONIPAT	138881	4804	19304	3.46%
21	YAMUNANAGAR	154748	4717	16556	3.05%
Total :		2937501	278300	1150461	9.47%

मास जनवरी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आदेश प्राप्त हुए थे कि जो आधार कार्ड बार-बार दोहराए जा रहे हैं उन्हें गेहूँ/चीनी/तेल की एलोकेशन न की जाए,

जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	मास	ड्रूप्लीकेट आधार कार्ड की संख्या जिनको गेहूँ जारी नहीं किया गया।	एलोकेशन (मात्रा टनों में)	सबसिडी (रुपये 16000 प्रति टन)
1.	फरवरी 2016	1386461	6932.30	रुपये 11.09 करोड़
2.	मार्च 2016	1386461	6932.30	रुपये 11.09 करोड़
3.	अप्रैल 2016	854712	4273.56	रुपये 6.84 करोड़
4.	मई 2016	854712	4273.56	रुपये 6.84 करोड़
5.	जून 2016	1065329	5326.64	रुपये 8.52 करोड़
कुल			27738.36	रुपये 44.38 करोड़

इस प्रकार मास फरवरी से जून 2016 तक कुल 27738.36 टन गेहूँ की बचत हुई है जिसके विरुद्ध रुपये 44.38 करोड़ सबसिडी की भी बचत हुई है।

इसके अतिरिक्त टी0पी0डी0एस0 स्कीम के तहत कुल 11.06 लाख राशन कार्ड जिन पर विभाग द्वारा मिट्टी के तेल का आबंटन 7 लीटर प्रति राशन कार्ड किया जाता रहा था, को सरकार द्वारा लिये गये निर्णय कि जिन ए0ए0बाई0/बी0पी0एल0 कार्डधारको के पास एल0पी0जी0 की सुविधा है, को मिट्टी के तेल का आबंटन बन्द कर दिया जाए, के फलस्वरूप मास जनवरी, 2016 से अब तक निम्न बचत हुई:-

मास	एल0पी0जी0 वाले कार्ड धारक	एल0पी0जी0 कार्डधारको को आबंटित की जाने वाली मात्रा	बचत
जनवरी, 2016	412804	2889628	9.19 करोड़
फरवरी, 2016	520474	3643318	11.59 करोड़
मार्च, 2016	520474	3673318	11.59 करोड़
अप्रैल, 2016	520474	3673318	11.59 करोड़
मई, 2016	520474	3673318	11.59 करोड़
जून, 2016	520474	3673318	11.59 करोड़
कुल बचत			67.14 करोड़

उत्तर 12

खाद्य एवं पूर्ति विभाग में नियमित तौर पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की स्वीकृत/भरे हुए तथा रिक्त पदों से सम्बन्धित सूचना अनुबन्ध 'क' पर उपलब्ध है। विभाग द्वारा बाहरी स्रोतों से सेवा प्राप्त कर रहे कार्यरत कर्मचारियों के बारे में वर्णन किया जाता है कि राज्य सरकार की outsourcing policy दिनांक 01.09.2006 में अंकित प्रावधानानुसार पार्ट-1 अनुसार जहाँ पर कार्य पूर्ण करने के लिए विभाग में कोई पद स्वीकृत न हो, के अनुसार रखे गये कर्मचारियों का जिलावार विवरण अनुबन्ध 'ख' पर उपलब्ध है।

इसी प्रकार राज्य सरकार की outsourcing policy दिनांक 01.09.2006 में अंकित प्रावधानुसार पार्ट-11 अनुसार जहां पर कार्य पूर्ण के लिए विभाग में पद स्वीकृत हो के अनुसार रखे गये कर्मचारियों का जिलावार विवरण अनुबन्ध 'ग' पर उपलब्ध है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार की SIT Policy दिनांक 17.03.2010 के अनुसार विभाग में स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध रखे गये कर्मचारियों का जिलावार विवरण अनुबन्ध 'घ' पर उपलब्ध है।

विभाग खादान के रख-रखाव एवं सुरक्षा के लिए सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से चौकीदार तथा पार्ट टाइम स्वीपर कर्मचारी रखता है। माननीय कमेटी द्वारा दिनांक 22.11.2016 को हुई बैठक में दिये निर्देश अनुसार outsourcing policy के तहत रखे जाने वाले अस्थाई पी0आर0 चौकीदारों व पार्ट टाइम स्वीपरों की नीति तथा अन्य विवरण इस प्रकार से है :-

मुख्य सचिव हरियाणा द्वारा दिनांक 01.09.2006 को outsourcing policy जारी की गई थी। जिसमें निर्देश दिए गए थे कि ग्रुप सी और डी में कोई भी Adhoc/Contract/Daily basis पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके स्थान पर outsourcing policy के आधार पर आवश्यकता अनुसार सेवा ली जाए।

Outsourcing policy के पॉलिसी पार्ट-1 अनुसार जहां पर विभाग में स्वीकृत पद नहीं है वहां पर un-skilled i.e. chowkidars, security guard without weapon, belldar, process service, sewadars, maalis, sweepers etc के लिए outsourcing policy के आधार पर सेवाएं ली जाएं। Outsourcing policy के पॉलिसी पार्ट-11 की नीति अनुसार विभाग में स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध अनुबंध आधार पर ग्रुप सी व डी कर्मचारी रोजगार कार्यालय तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित करके एक वर्ष की अवधि या नियमित रूप में जब तक स्थाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं होती तब तक सरकार द्वारा समय-2 पर नियत वेतन पर रखे जाते हैं।

उक्त Outsourcing policy पॉलिसी पार्ट-1 सेवाएं के लिए विभाग द्वारा बजट में प्रावधान किया जाए और टैण्डर द्वारा ये सेवाएं ली जाती हैं तो वित्त विभाग की अनुमति की आवश्यकता भी नहीं है। इसके उपरान्त इस नीति में समय-2 पर बदलाव सरकार द्वारा किए गए हैं। अब मुख्य सचिव हरियाणा की हिदायते 43/5/2001-1जी0एस0 दिनांक 01.09.2006 अनुसार पहले सर्विस प्रोवाइडर की नियुक्ति छः मास के लिए ओपन टैण्डरों द्वारा की जाती थी। अब मुख्य सचिव हरियाणा की संशोधित हिदायते 16/7/2015-1जी0एस0-11, दिनांक 06.04.2015 अनुसार सर्विस प्रोवाइडरों की नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाए तथा आवश्यकता हो तो छः मास के लिए बढ़ा दी जाए।

जहां तक खाद्य एवं पूर्ति विभाग का सम्बन्ध है विभाग में गोदामों/पलिनथों में भण्डारण किए जाने वाले गेहूँ के स्टॉक की रखवाली/रख-रखाव के लिए आवश्यकता अनुसार पद स्वीकृत नहीं है। गेहूँ का भण्डारण किराए के गोदामों/पलिनथों पर भी करना पड़ता है। जिसके लिए अस्थाई पी0आर0 चौकीदारों/पार्ट टाइम स्वीपरों के लिए सर्विस प्रोवाइडरों को नियुक्त किया जाता है। सर्विस प्रोवाइडरों की नियुक्ति जिला नियन्त्रक की अध्यक्षता में कमेटी गठित करके की जाती है। इसके लिए जिला

नियन्त्रक द्वारा समाचार पत्रों में आवश्यक विज्ञापन प्रकाशित करके टैण्डर आमंत्रित किए जाते हैं और टैण्डर उपरान्त जिला नियंत्रक द्वारा गठित कमेटी की सिफारिश पर मुख्यालय द्वारा सर्विस प्रोवाइंडर नियुक्त करने की प्रशासनिक अनुमति प्रदान की जाती है। अस्थाई पी0आर0 चौकीदारों व पार्ट टाइम स्वीपरों का वेतन उपायुक्त द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार दिया जाता है तथा इनका EPF and ESI, Act 1952 की कटौती भी सरकार की हिदायतों के अनुसार की जाती है।

विभाग द्वारा खरीदे गए गेहूँ की सुरक्षा के लिए अस्थाई पी0आर0 चौकीदार रखने के लिए विभिन्न जिलों में रखे गए सर्विस प्रोवाइंडरों की सूची संलग्न है। इसके अतिरिक्त जिलों से प्राप्त सूचना अनुसार दिनांक 30.11.2016 को सभी जिलों में कुल 807 पी0आर0 अस्थाई चौकीदार व 129 पार्ट टाइम स्वीपर सर्विस प्रोवाइंडर के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। इनकी संख्या कम व ज्यादा होती रहती है जोकि गेहूँ के स्टॉक की स्थिति पर निर्भर है। इनका जिलावार अस्थाई पी0आर0 चौकीदार व पार्ट टाइम स्वीपरों की सूची संलग्न है। इसके अतिरिक्त जिन सर्विस प्रोवाइंडरों द्वारा पिछले पांच वर्षों से कार्य किए हैं उनकी सूची भी संलग्न है।

उत्तर 13

हरियाणा राज्य में भारत सरकार ने वर्ष, 2019-20 तक तीन चरणों में 9.50 लाख मीट्रिक टन क्षमता के साईलोज बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रथम चरण में 3 लाख मीट्रिक टन, द्वितीय चरण में 2 लाख मीट्रिक टन तथा तृतीय चरण में 4.5 लाख मीट्रिक टन क्षमता के साईलोज पी0पी0पी0 मोड पर बनाए जाने हैं। प्रथम व द्वितीय चरण के साईलोज भारतीय खाद्य निगम तथा तृतीय चरण के साईलोज राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने हैं। इस बारे में भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्टील साईलों बनाने बारे स्टोरेज गैप की पहचान के लिए सभी खरीद संस्थाओं के नोडल अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है। प्रथम चरण के लिए भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा 3.00 लाख एम0टी0 क्षमता के साईलों बनाने के लिए टैण्डर आमंत्रित किए गए हैं। टैण्डर में प्राप्त हुए आवेदनों की सूचना विभाग में प्राप्त नहीं होती है। वह केवल भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली के पास ही है। राज्य सरकार द्वारा केवल 4.5 लाख एम0टी0 क्षमता के साईलों का निर्माण किया जाना है। जिसके लिए स्थानों की पहचान को अंतिम रूप दिया जाना शेष है।

उत्तर 14

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अनुसार हरियाणा राज्य के बी0पी0एल0 परिवारों की महिलाओं को खाना पकाने के लिए प्रदूषण मुक्त स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाने हेतु SECC-2011 में शामिल 13,53,710 लाख बी.पी.एल. परिवारों में से 2,87,195 बी0पी0एल0 परिवारों को PMUY के तहत गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए गये हैं। राज्य में कुल 11,10,223 बी.पी.एल./ एवाई परिवार हैं। राज्य में 1 अप्रैल, 2015 से पहले 2,92,081 तथा Corporate Social Responsibility (CSR) (1st April, 2015 to 31.3.2016) स्कीम के तहत बी.पी.एल. परिवारों को 1,85,176 गैस कनेक्शन जारी किये गये। शेष 3,45,771 परिवारों को दिनांक 31.3.2017 तक गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है जिससे हरियाणा राज्य को सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार मिट्टी तेल मुक्त

राज्य बनाया जा सके।

अनुबन्ध- - SECC-2011 में शामिल 13,53,710 लाख परिवार

अनुबन्ध-बी - 11.10 लाख बी.पी.एल. परिवार

अनुबन्ध-सी - बी.पी.एल.परिवारों को जारी किये गये गैस कनेक्शनों का विवरण

उत्तर 15

पेट्रोल एवं डीजल एक मुक्त व्यापार पदार्थ है। इसका वितरण तेल कम्पनियों द्वारा डीलरों की मांग के आधार पर किया जाता है। तेल कम्पनियों द्वारा विभाग को सूचित किया गया है कि सामान्यता: एक पेट्रोल पम्प अपनी भण्डारण क्षमता का कम से कम 30-40 प्रतिशत भण्डार रखता है।

(1) भारत सरकार के नियंत्रण आदेश the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005 की प्रति "अनुबन्ध-डी" पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा पेट्रोल पम्प चैक करने की हिदायतें दिनांक 30.04.2013 की प्रति "अनुबन्ध-ई" पर संलग्न है।

(3) मास 4/2015 से 11/2016 के दौरान 2446 पेट्रोल व डीजल के सैम्पल लिये गये जिनमें से 2072 सैम्पल ठीक पाये गये और 374 की रिपोर्ट संबंधित लैब से अपेक्षित है। विभाग द्वारा लिये गये सैम्पलों की सूची "अनुबन्ध-एफ" पर संलग्न है।

(4) पेट्रोल व डीजल के सैम्पल ड्रा करने उपरांत जिस-जिस लैबोरेट्री में भेजे जाते हैं उसका विवरण "अनुबन्ध-जी" पर उपलब्ध है।

(5) माप तोल संगठन के अनुसार वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में पेट्रोल पम्पों के विरुद्ध की गई कार्यवाही रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

2015-16		
	Case Booked	Compounding Fees
Petrol Pump	24	2,33,000
LPG Dealer	14	3,43,000
2016-17 (01 04 2016 to 30.11 2016)		
	Case Booked	Compounding Fees
Petrol Pump	16	1,30,000
LPG Dealer	10	1,29,000

(6) जिलावार पेट्रोल पम्पों (कम्पनीवार) की सूची "अनुबन्ध-एच" पर संलग्न है।

उत्तर 16

तेल कम्पनियों द्वारा एल.पी.जी. गैस एजेंसिज की क्षमता निर्धारित की गई है, जोकि निम्न प्रकार से है:-

Type of Distributionship area	Population as per census 2011	Refill Ceiling Limit per month	Refill Sale per month per Feasibility limit
Sheheri Vitrak	Cities with population > 40 lakh	20,000	10,000
	Cities with 20 to 40 lakh population	15,000	7,500
	Cities with 10 to 20 lakh population	12,000	6,000

Rurban Vitrak	Towns with < 10 lakh population	10,000	5,000
Gramin Vitrak	Village/Cluster of villages	5,000	2,500
Durgam Khetnya Vitrak	Village/Cluster of villages	1,500	600

उक्त बारे सूचना "अनुबंध-आई" पर उपलब्ध है।

प्रदेश में कुल 48,71,860 गैस उपभोक्ता हैं जिनमें से 44,65,943 द्वारा गैस सब्सिडी प्राप्त की जा रही है। 3,31,836 उपभोक्ताओं ने अपनी गैस सब्सिडी स्वतः छोड़ रखी है जिसका जिलावार पूरा विवरण "अनुबंध-जे" पर उपलब्ध है।

- (1) भारत सरकार के नियंत्रण आदेश the Liquified Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000 की प्रति "अनुबंध-के" पर संलग्न है।
- (2) विभाग द्वारा एल0पी0जी0 की चैकिंग हेतु जारी की गई हिदायतें दिनांक 13.10.2014 की प्रति "अनुबंध-एल" पर संलग्न है।
- (3) जिलावार एल0पी0जी0 वितरकों की सूची "अनुबंध-एम" पर संलग्न है।
- (4) एल0पी0जी0 के अनाधिकृत प्रयोग के कारण वर्ष 2015-16 में विभाग व पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही:-

2015-16	खाद्य विभाग द्वारा जन्त सिलेण्डरों की संख्या	विभाग द्वारा पुलिस में दर्ज करवाये गये मामले
	103	0
2016-17	86	1

2015-16	पुलिस विभाग द्वारा जन्त सिलेण्डरों की संख्या	पुलिस विभाग द्वारा दर्ज किये गये मामले
	544	24
2016-17	10	1

- (5) मास 4/2015 से 11/2016 के दौरान 560 गैस एजेंसियों की चैकिंग की गई। 3 गैस एजेंसियों के विरुद्ध पाई गई कमियों के आधार पर कार्यवाही करने हेतु ऑयल कम्पनी को लिखा गया। 10 गैस एजेंसियों को भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। अनुबन्ध- 'एन'

उत्तर 17

दिनांक 15.12.2016 की विवरणी अनुसार विभाग का 20192 एम0टी0 गेहूँ खुले में भण्डारित है तथा 230218 एम0टी0 गेहूँ कवर्ड गोदामों में भण्डारित है जो गेहूँ खुले में भण्डार किया गया है उसको सुरक्षित रखने के लिए कवरों से ढकने व समय-2 पर दवाईयों का छिड़काव करने के निर्देश जिला नियन्त्रकों को दिए हुए है।

वर्ष 2014-15 में करनाल/जुण्डला केन्द्र पर 723 एम0टी0, जुण्डला में 8094 एम0टी0 तथा ईस्माईलाबाद (कुरुक्षेत्र) में 3800 एम0टी0 कुल 12617 एम0टी0 गेहूं खराब हुआ था। वर्ष 2015-16 में जुण्डला करनाल में 360 एम0टी0 गेहूं खराब हुआ है।

उत्तर 18

1. राज्य में वर्ष 2008 में 12.97 लाख बी.पी.एल./एएवाई परिवारों को राशन कार्ड जारी किये गये थे। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय के आदेशों की पालना में वर्ष 2011 में ग्रामीण विकास विभाग व शहरी निकाय विभाग द्वारा पुनः सर्वे करवाया गया जिसमें 2.07 लाख परिवार अपात्र पाये गये।
2. ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा द्वारा सूचित किया गया है कि 83,062 बी.पी.एल. राशन कार्ड (अनुबंध- 'ओ') अपात्र पाये गये जिन्हें सूची से delete कर दिया गया। इसी प्रकार शहरी निकाय विभाग, हरियाणा द्वारा सूचित किया कि 1,23,634 लाख परिवार (अनुबंध- 'पी') अपात्र पाये गये जिन्हें बी.पी.एल. सूची से delete कर दिया गया।
3. वर्ष 2014 तक प्रदेश में 4,75,165 केन्द्रीय बी.पी.एल., 3,92,195 राज्य बी.पी.एल. व 2,65,961 (7821 बेघर परिवारों सहित) ए.ए.वाई. परिवार थे। इस प्रकार कुल 11,33,321 बी.पी.एल. परिवार थे। जिलावार राशन कार्डों की संख्या "अनुबंध- 'क्यू'" पर संलग्न है।
4. जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों से प्राप्त रिपोर्टनुसार वर्ष 2014 से 5033 बी.पी.एल. (4563 BPL+470 AAY) राशन कार्डों की बढ़ौतरी हुई है। (अनुबंध- 'आर')
5. जिला स्तर पर बी.पी.एल. राशन कार्डों का inclusion/exclusion का कार्य निरन्तर चलता रहता है। कुल 11,33,321 बी.पी.एल. परिवार को End-to-End Computerisation के तहत digitized/verified किया गया, तत्पश्चात् यह संख्या 11,10,223 तक सीमित रह गई है। (अनुबंध 'एस')

उत्तर 19

• यदि क्रमांक एफ.जी.-3-2005/5796 दिनांक 07.04.2005 के तहत गठित नमूने लेने हेतु कमेटी का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

खाद्य विभाग तथा एजेंसी के गोदामों से खाद्यान्न की डिलीवरी लेते समय कमेटी द्वारा संयुक्त नमूने लिए जाएंगे। इस कमेटी के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

क) सम्बन्धित जिले का जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक/अधिकारी या सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी।

ख) सम्बन्धित जिले का जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक कान्फैड।

ग) सम्बन्धित डिपूथारक एसोसिएशन का प्रतिनिधि।

घ) खाद्य एवं पूर्ति विभाग का मुख्य विश्लेषक।

खाद्य वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उक्त कमेटी का गठन किया हुआ है जो प्रत्येक मास डिपू पर राशन आने से पूर्व उसको चैक करते हुए नमूने रखते हैं। यदि किसी डिपू पर खराब गोहूँ बारे शिकायत प्राप्त होती है तो उसे तुरन्त ही जिला स्तर पर बदल दिया जाता है।

खाद्य सामग्री की क्वालिटी चैक करने के मापदण्ड "अनुबन्ध- टी" पर पर रखे हुए हैं।

उत्तर 20

"द हरियाणा कंट्रोल आफ ब्रिक्स सप्लाय आर्डर, 1972" में ईटों के आकार, वजन, कीमत और ईटों की गुणवत्ता से सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है परन्तु इस बारे पीओडब्ल्यू0डी0 (बी एंड आर) विभाग की हिदायतें क्रमांक 4114 दिनांक 09.09.2005 है, प्रति अनुबन्ध-"यू" पर संलग्न है", जिसमें ईटों/टाईलों के साईज का निम्नानुसार उल्लेख है:-

i) Size of bricks :-

22.86 cm x 11 11 cm x 6.83 cm

A tolerance upto +- 6 5 mm in length +- 3 00mm width and +-3.00 mm in thickness shall be permitted. A frog 65 mm deep shall be provided on the upper face.

ii) Size of Brick Tiles :-

a) Tiles for flooring tile facing & tile brick masonry Size 22.86 cm x 11.43 cm x 3.81 cm.

b) Tiles for 1st class Mud roofing (not in common use as on today)
Size 30 48 cm x 15 24 cm x 3.18 cm.

c) Tiles for second class Mud roofing for looring and canal lining
Size 30.48 cm x 15 24 cm x 5 08 cm.

Permissible tolerance limit in size of brick tiles +-6.5mm in length +- 3.00mm for width +-1.5 mm in thickness.

अनुबन्ध 'क'

Status of Staff as on 01.1.2017

Field Cadre Class-B & C

Category	Sanctioned	Filled	Vacant	Promotion	Direct	Remarks
DFSC	23	18	05	01	04	Recommendation received from HPSC for 2 DFSC out of which 1 DFSC has been appointed.
DFSO	23	15	08	02	06	Recommendation received from HPSC for 3 DFSO
Supdt.	21	13	08	08	00	
AFSO	83	53	30	04	26	Requisition of 24 posts has already been sent & 2 posts kept pending for SBC
Inspector	317	263	54	06	48	Requisition of 48 posts has already been sent.
SIFS	317	175	142	53	89	Requisition of 80 posts has already been sent
Acctt	58	58	00	00	00	
S.O	21	12	09	00	09	FD cadre post
Asstt	16	13	03	03	00	
STA	14	00	14	14	00	
Steno-Typist	21	03	18	00	18	Requisition of 16 posts has already been sent & 1 post kept pending for SBC
Clerk	241	111	130	32	98	Requisition of 48 posts has already been sent
Auditor	80	55	25	00	25	Requisition of 24 posts has already been sent
Picker	28	00	28	28	00	All the Lab. have been closed. Therefore the requisition has not been sent to HSSC

Driver	21	21	00	00	00	
Head Analyst	33	18	15	04	11	All the Lab. have been closed Therefore the requisition has not been sent to HSSC.
Junior Analyst	58	01	57	38	19	All the Lab. have been closed. Therefore the requisition has not been sent to HSSC
Total	1375	829	546	193	353	

Class-IV as on 01.1.2017

Category	Sanctioned	Filled	Vacant	Promotion	Direct	Remarks
Daftn	19	12	07	07	0	
Peon	156	88	68	00	68	Requisition of 58 posts has been sent.
P.R. Chowkidar	284	145	139	0	139	Requisition of 127 posts has been sent
Sweeper cum Chowkidar	21	05	16	0	16	Requisition of 15posts has been sent
Total	480	250	230	7	223	

Legal Metrology Class-III Officials As on 01.1.2017

Category	Sanctioned	Filled	Vacant	Promotion	Direct	Remarks
DCLM	1	1	0	0	0	
ACLM	4	4	0	0	0	
Dy.Suptd	1	1	0	0	0	
Asstt.cum Acctt	1	1	0	0	0	
Equipment Repairer	1	1	0	0	0	
Inspector	32	19	13	0	13	Requisition of 12 posts has already been sent & 1 post kept pending for SBC
Manual Asstt	33	24	9	2	7	Requisition of 07 posts has been sent.

Steno	1	1	0	0	0	
Clerk	6	2	4	0	4	Requisition of 3 posts has already been sent & 1 post kept pending for SBC
LMV Driver	1	0	1	0	1	Requisition of 01 posts has been sent
HMV Driver	1	0	1	0	1	Requisition of 01 posts has been sent.
Total	82	54	28	2	26	

Legal Metrology Class-IV. As on 01.01.2017

Category	Sanctioned	Filled	Vacant	Promotion	Direct	Remarks
Daftri	1	0	1	1	0	
Peon	5	0	5	0	5	Requisition for 4 posts has been sent to Haryana Group "D" employees selection Committee No. 7E(1)-09/11971, dated 01-06-2009
Chowkidar	1	1	0	0	0	
Helper	1	0	1	0	1	Rules are yet to be framed
Total	8	1	7	1	6	

District Food & Supplies Controller

Sanctioned post 23 (Direct 11 and By promotion 12)

Filled. 18 (Direct quota 7 and Promotion 11)

Vacant 5 (Direct 4 and by promotion 1)

Direct Quota	Remarks	Promotion Quota	Remarks
7	Charge Given to Gurugram Division under NFSA =1 Posted at H Q. 2 Posted in Distt =4 (Panchkula, Rohtak, Ambala and Karnal)	11	Charge Given to Hisar Division under NFSA =1 Under Suspension =3 Deputation =1 Posted in Distt =6 (Rewari, Gurugram, Fatehabad, Mewat, Bhiwani and Jind)

In remaining District 11 District Food & Supplies Officer posted after giving the charge of DFSC namely.

Faridabad, Palwal, Hisar, Sirsa, Kaithal, Kurukshetra, Yamuna Nagar, Narnaul, Sonapat, Panipat and Jhajjar

vacancy position of District Food & Supplies Controller as under -

Sr. No.	Name of Distt	Sanctioned post	Filled	Vacant	Remarks
1	Ambala	1	1	-	
2	Bhiwani	1	1	-	
3	Faridabad	1	-	1	DFSO look after the work of DFSC
4	Fatehabad	1	1	-	
5.	Gurugram	1	2	-	1 DFSC look after the work of Gurugram Division under NFSA
6.	Hisar	1	1	-	1 DFSC look after the work of Hisar Division under NFSA
7.	Jind	1	1	-	
8	Jhajjar	1	-	1	DFSO look after the work of DFSC
9	Kaithal	1	-	1	-do-
10	Karnal	1	1	-	
11	Kurukshetra	1	-	1	DFSO look after the work of DFSC
12	Mewat	1	1	-	
13	Narnaul	1	-	1	DFSO look after the work of DFSC
14	Palwal	1	-	1	-do-
15	Panipat	1	-	1	-do-
16.	Panchkula	1	1	-	
17.	Rewari	1	1	-	
18	Rohtak	1	1	-	
19	Sirsa	1	-	1	DFSO look after the work of DFSC
20	Sonepat	1	-	1	-do-
21.	Y.Nagar	1	-	1	-do-
22	H Q	2	2	-	

Staff Position of Distt. Food & Supplies Officer

Sanctioned. 23 (Direct 11 and By promotion 12)

Filled . 15 (Direct 5 and by promotion 10)

Vacant .8 (Direct 6 and by promotion 2)

Direct Quota	Remarks	Promotion Quota	Remarks
5	Deputation with Punjab Govt.= 1 Posted in District Panchkula as DFSO =1 Posted in Distt. as DFSC =3 (Kaithal, Sirsa and Fandabad/ Palwal)	10	Posted at HQ =1 Posted in Distt.=2 (Ambala and Yamunagar) Posted in Distt. as DFSC= 7 (Hisar, Kurukshetra, Yamuna Nagar, Namaul, Sonapat, Panipat and Jhajjar)

As per Above the vacancy position of Distt. Food & Supplies Officer as under:-

Sr. No.	Name of Distt	Sanctioned post	Filled	Vacant	Remarks
1.	Ambala	1	1	-	
2.	Palwal	1	-	1	
3.	Fandabad	1	-	1	DFSO look after the work of DFSC
4.	Fatehabad	1	-	1	
5.	Gurugram	1	-	1	
6.	Hisar	1	-	1	DFSO look after the work of DFSC
7.	Jind	1	-	1	
8	Jhajjar	1	-	1	DFSO look after the work of DFSC
9.	Kaithal	1	-	1	-do-
10	Kamal	1	-	1	
11	Kurukshetra	1	-	1	DFSO look after the work of DFSC
12	Mewat	1	-	1	
13.	Namaul	1	-	1	DFSO look after the work of DFSC
14.	Palwal	1	-	1	-do-
15.	Panipat	1	-	1	-do-
16.	Panchkula	1	1	-	
17	Rewari	1	-	1	
18	Rohtak	1	-	1	
19.	Sirsa	1	-	1	DFSO look after the work of DFSC
20.	Sonepat	1	-	1	-do-
21	Y.Nagar	1	-	1	-do-
22.	H Q.	2	1	1	

अनुबन्ध 'ख'

DISTRICT WISE LIST OF TEMPORARY PR CHOWKIDAR AND PART TIME SWEEPER AS ON 30.11.2016

SR. NO.	NAME OF DISTRICT	NO. OF CHOWKIDAR ENGAGED	PART TIME+ SWEEPER ENGAGED
1	Ambala	36	02
2	Bhiwani	33	11
3	Fardabad	9	01
4	Fatehabad	51	11
5	Gurgaon	00	00
6	Hisar	42	07
7	Jhajjar	10	02
8	Jind	58	04
9	Kaithal	53	09
10	Karnal	234	45
11	Kurukshetra	90	11
12	Narnaul	06	02
13	Palwal	44	08
14	Panipat	13	01
15	Rewari	10	01
16	Rohtak	13	02
17	Sirsa	47	09
18	Sonapat	14	03
19	Yamuna Nagar	44	00
20	Panchkula	00	00
21	Mewat	00	00
	Total	807	129
	Grand Total		936

अनुबन्ध 'ख'

SR. NO.	NAME OF DISTRICT	NO. OF EMPLOYEES ENGAGED (DATA ENTRY OPERATOR)
1	Ambala	4
2	Bhiwani	1
3	Fardabad	1
4	Fatehabad	1
5	Gurgaon	-
6	Hisar	-
7	Jhajjar	-
8	Jind	3
9	Kaithal	5
10	Karnal	3
11	Kurukshetra	3
12	Mewat	-
13	Narnaul	1
14	Palwal	-
15	Panipat	1
16	Panchkula	1
17	Rewari	-
18	Rohtak	1
19	Sirsa	2
20	Sonapat	1
21	Yamuna Nagar	4
	Total	32

अनुबन्ध 'ग'

SR. NO.	NAME OF DISTRICT	NO. OF EMPLOYEES ENGAGED	
		PROGRAMMER THROUGH NICS/NIC	JUNIOR PROGRAMMER
1	Ambala	1	5
2	Bhiwani	1	1
3	Faridabad	1	1
4	Fatehabad	1	2
5	Gurgaon	1	3
6	Hisar	1	5
7	Jhajjar	1	2
8	Jind	1	3
9	Kathal	1	6
10	Karnal	1	5
11	Kurukshetra	1	5
12	Mewat	1	1
13	Narnaul	1	1
14	Palwal	1	1
15	Panipat	1	2
16	Panchkula	1	2
17	Rewari	1	1
18	Rohtak	1	1
19	Sirsa	1	1
20	Sonapat	1	1
21	Yamuna Nagar	1	3
	Total	21	52

Annexure-"A"

SR. NO.	NAME OF DISTRICT	COUNT OF SECC HOUSEHOLD
1	Ambala	56495
2	Bhiwani	82535
3	Farrdabad	83923
4	Fatehabad	60064
5	Gurgaon	79365
6	Hisar	83799
7	Jhajjar	35978
8	Jind	76313
9	Kaithal	72740
10	Karnal	91344
11	Kurukshetra	59114
12	Mahendergarh	43372
13	Mewat	75462
14	Palwal	59282
15	Panipat	61088
16	Panchkula	29171
17	Rewari	42162
18	Rohtak	48799
19	Sirsa	70833
20	Sonipat	65512
21	Yamuna Nagar	76359
	Total	1353710

Annexure-"B"

SR.NO.	DISTRICT	AAY	SBPL	CBPL	(AAY+SBPL+CBPL)
		RATION CARDS	RATION CARDS	RATION CARDS	RATION CARDS
1	Ambala	15155	33247	24004	72406
2	Bhiwani	16756	28771	35853	81380
3	Fatehabad	6205	41729	14032	61966
4	Fatehabad	11298	24574	13616	49488
5	Gurgaon	9430	13502	12294	35226
6	Hisar	17519	16749	44326	78594
7	Jhajjar	8643	5744	15232	29619
8	Jind	17700	35671	13223	66594
9	Kaithal	18110	22021	18210	58341
10	Karnal	12772	23306	30937	67015
11	Kurukshetra	12700	10779	27284	50763
12	Mahendergarh	16965	11870	20339	49174
13	Mewat	10779	14705	13501	38985
14	Palwal	10049	6588	19285	35922
15	Panipat	8965	11998	27067	48030
16	Panchkula	2686	3944	4309	10939
17	Rewari	13885	19784	14856	48525
18	Rohtak	5605	15787	21480	42875
19	Sirsa	21159	18096	26657	65912
20	Sonipat	10139	19963	24598	54700
21	Yamuna Nagar	10022	19608	34139	63769
GRAND TOTAL		256545	398436	455242	1110223

Annexure-C

"KEROSENE FREE HARYANA"**FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT, GOVERNMENT OF HARYANA**

The details of BPL families and LPG connections issued in Haryana (All 21 districts)

1	Total number of BPL families	11,10,223
2	No of LPG connections issued under CSR (1 st April, 2015 to 31 th March, 2016)	1,85,176
3	No. of LPG connections issued before CSR (Before 1 st April, 2015)	2,92,081
4	LPG connection issued under PMUY in 21 st District (1 May, 2016 to till date) PMUY+State Fund	2,87,195 (2,41,121+46074)
5	Total connections issued so far (2+3+4)	7,64,452
6	Remaining BPL families to be issued LPG connections	3,45,771

Verfied forms handed over to LPG dealers in all 21 Distt.	52,472
---	--------

The figure in respect of eight District of Haryana declared "kerosene Free"

1	No. of BPL ration card	3,77,767
2	LPG connection released before PMUY	2,01,805
3	Connection released under PMUY+State Fund	89,950 (72,652+17,298)
4	Total LPG connections released (2+3)	2,91,755
5	Balance families to be covered	86,012
6	No. of families LPG connection not to be provided due to duplicacy reported by Oil Marketing Companies (OMCs)	36,634
7	Remaining BPL families to be issued LPG connections	49,378
8	No of villages in the 8 Districts	2943
9	Camps organized so far in these 8 Districts	4261
10	Total No. of villages in Haryana	6841
11	Total No. of camps organized in Haryana	6611

- Note: 1 Atleast one camp has been organized in every village by 31st October, 2016
 2 The remaining 13 Districts will be made "Kerosene Free" by 31st March, 2017
 3 Kerosene supply to about 5 lac BPL families has been discontinued since January, 2016 which has resulted in accumulated saving of Rs. 150.64 crore till date.

Annexure-D

--- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and supersession of Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and prevention of Malpractices) Order, 1998 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Order, namely -

1. Short title, extent and commencement:-

- (1) This order may be called the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and prevention of Malpractices) Order, 2005,
- (2) It extent to the whole of India,
- (3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette

2. Definitions -In this Order, unless the context otherwise requires,

- (a) "adulteration" means the introduction of any foreign substance into motor spirit or high speed diesel illegally or unauthorisedly with the result that the product does not confirm to the requirements of the Bureau of Indian Standards specifications or any other requirement notified by the Central Government from time to time,
- (b) "authorized officer" means an officer authorized under the provisions of clause;
- (c) "consumer" means a person who purchases product form an oil company or a dealer appointed by an oil company and stores or utilizes the product for his own consumption and include his representatives, employees and agents;
- (d) "dealer" means a person duly appointed by an oil company to purchase, receive, store and self motor spirit and high speed diesel oil whether or not in conjunction with any other business and shall his representatives, employees and agents,
- (e) "high speed diesel" means any hydrocarbon oil, excluding mineral colza oil and turpentine substitute, which means the requirements of Bureau of Indian Standards specification number IS-1160,
- (f) "malpractices" shall include the following acrs of omission and commission in respect of Motor Spirit and High Speed Diesel -
 - (i) Adulteration,
 - (ii) Pilferage,
 - (iii) stock variation,
 - (iv) unauthorized exchange,

- (v) unauthorized purchase,
 - (vi) unauthorized sale,
 - (vii) unauthorized possession,
 - (viii) over-charging,
 - (ix) sale of off-specification product, and
 - (x) short delivery,
- (g) "motor spirit" means any hydrocarbon oil, excluding crude mineral oil, which meets the requirements of Bureau of Indian Standards specification number is 2796,
- (h) "oil company" means Indian oil corporation Limited, the Hindustan Petroleum Corporation Limited, the Bharat Petroleum Corporation Limited, the IDP Co Limited or any person, firm or company duly authorized by the Central Government who is engaged in marketing and sale of motor spirit of high speed diesel directly to consumers or dealers in accordance with the stipulations laid down by the Central Government from time to time,
- (i) "pilferage" means stealing or attempt to steal product from a container used for transportation of the product or from a receptacle used for storage of the product and shall include any unauthorised attempt or act of tampering with such container or receptacle,
- (k) "product" means motor spirit and high speed diesel,
- (l) "Schedule" means The Schedule appended to this Order,
- (m) "stock variation" means variation beyond the norms for permissible variation in stocks as specified in Schedule I;
- (n) "transporter" means a person duly authorized by an oil company, a dealer or a consumer, to transport motor spirit or high speed diesel and shall include his representatives, employees and agents,

3. Product supply and transportation:-

- (1) The product from the supply point shall be transported by the transporter in a container or tank-truck certified to be fit by the explosives authorities, transport authorities and oil company to carry the product with accurate calibration as certified by the weight and measures authorities and supported by delivery documents and deliver the same to the storage or dispensing point in the same condition as delivered to him by the originating supply point both in respect of quality and quantity.
- (2) the transporter shall ensure that the product is transported only in containers or tank truck which is properly sealed and locked

4. Restriction on marketing of motor spirit and high speed diesel-

No person, other than those authority by the Central Government, shall market and sell motor spirit or high speed diesel to consumers or dealers.

5. Grant of authoriation to market motor spirit and high speed diesel-

- (1) who so ever diesel to secure authorization to market and sell motor spirit and high speed diesel shall submit an application to the Central Government as per the form given in Schedule II alongwith a fee of ruppe ten lacs either by way of banker's cheque or demand draft in favour of pay and Account Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas payable at New Delhi
- (2) After scrutiny of the application, the Central Government shall, if it is satisfied with the details furnished by the applicant, after requiring the applicant to furnish bank guarantee for an amount specified by the Government, issue authorization to market motor spirit and high speed diesel indication the terms and conditions of such authorization

6. Supply of motor spirit and high speed diesel blended with ethanol and Bio-Diesel.

The Central Government may by an order, make it mandatory to supply motor spirit and high speed diesel blended with a specified quantity of anhydrous ethanol and or bio-diesel in the whole or any part of the territory of a State of whole of the territory of the Indian Union.

7. Power of search and secure:-

Any Gazetted Officer of the Central Government or a State Government of any police Officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police duly authorised, by general or special order of the Central Government or a State Government, as the case may be, or any officer of the oil company not below the rank of sales officer, may, with a view to securing compliance with the prociisions of this Order, of for the purpose of satisfying himself that the Order or any order made there under has been complied with or there is reasen to believe that all or any of the provisions of this Order have been and are being or are about to be contravened

8. Sampling and product

The authorised under clause 7 shall draw the sample form the tank, nozzle vehicle or receptacle, as the case may be in clean aluminium containers, to check wheter density and other parameters of the product confirm to the requirements of Bureau of Indian Standard specificaiton number IS 2796 and IS 1460 for motor spirit and high speed diesel respectively. Where samples are drawn from retail outlet, the relevant tank-truck sample retained the dealer as per clause 3 (b) would also be collected for laboratory analysis

9. Power of Central Government to issue directions

The Central Government may, form time to time by a general or special order issue to any dealer, transporter or consumer or any other person, such directions as it considers necessary regarding storage, sale, transportation and diposal of motor spirit or high speed diesel and upon

the issue of such direction, such dealer, transporter of consumer shall be bound to comply therewith

10. Overriding effect

The Provision of this Order shall have overriding effect notwithstanding anything to the contrary contained in any order made by a state Government or by an Officer of such State Government before the commencement of this order except as respects anything done or omitted to be done there under before such commencement

Annexure-E

Subject:- Revised instunction regarding checking and sampling of petrol pumps.

With a view to ensure that no adulterated fuel/petrol/diesel is sold by any retailer outlet, District Food and Supplies Controllers, within their respective jurisdiction, will ensure regular checking of retail outlet of petrol and diesel and samples from each outlet be drawn twice in an year i.e once in every six months and sent to laboratories for analysis. In case any adulteration is established, police case be got registered immediately as a deterrent measure. These instructions will supersede the earlier instructions referred to above.

Annexure-F

Detail of petrol pump checking from 04/2015 to 11/2016

Sr. No	District	Petrol	Diesel	Result of samples (Report OK)	Result awaited	Samples Tested form (Name of Lab)	Action taken against petrol pump
1.	Ambala	11	29	40	0	IOC, Panipat	Nil
2	Bhiwani	1	43	0	44	IOCL, Panipat, HPCL, Panipat BPCL Panipat & Society for petroleum Lab. Noida	Nil
3.	Fardabad	21	24	45	0	Society for petroleum Lab. Noida	Nil
4	Fatehabad	303	210	513	0	IOCL, Panipat, HPCL, Panipat & BPCL Panipat	Nil
5.	Gurugram	47	96	143	0	Society for petroleum Lab Noida	Nil
6.	Hisar	0	13	1	12	SLC &IOC Panipat	Nil

7.	Jind	17	17	34	0	IOC, Panipat	Nil
8	Jhajjar	82	65	147	0	Society for petroleum Lab. Noida	Nil
9	Karnal	31	27	58	0	IOCL, Panipat, HPCL, Panipat & BPCL Panipat	Nil
10.	Kaithal	21	21	16	26	IOCL, Panipat, HPCL, Panipat & BPCL Panipat	Nil
11.	Kurukshetra	17	8	19	6	IOCL Ambala & HPCL Panipat	Nil
12.	Mewat	39	26	41	24	HPCL Gurugram & SFPL Noida	Nil
13.	Namaul	103	142	83	162	BPCL Panipat, HPCL Gurugram & IOCL Rewari	Nil
14.	Panipat	0	114	114	0	IOCL, Panipat, HPCL, Panipat & BPCL Panipat	Nil
15	Panchkula	60	62	120	2	IOCL Panipat, Ambala & BPCL Ambala	Nil
16	Palwal	4	4	8	0	Fuel Testing lab Noida	Nil
17.	Rewari	7	20	0	27	IOCL Karnawas & IOCL Bijwashaan	Nil
18.	Rohtak	50	54	92	12	Fuel testing lab Noida & HPCL Gurugram	Nil
19	Sirsa	0	0	0	0	Nil	Nil

20	Sonepat	408	216	596	28	Fuel testing lab Noida	Notice issued due to Failure of Tank Lorry (T T)Sampling of M/s Suraj Filling Station Sonepat Dated 14.03 2016
21	Yamuna Nagar	27	6	2	31	IOC Panipat	Nil
	Total	1249+1197= 2446		2072	374		

ANNEXURE-'G'**SCHEDULE-III**

See Clause 8(4)

Laboratories for testing of Petroleum Product Samples**1. Marketing and Refinery Laboratories of Oil Companies**

- (i) All the marketing (including Mobile Laboratories) and Refinery Laboratories of Bharat Petroleum Corporation Limited, Hindusthan Petroleum Corporation Limited, Indian Oil Corporation Limited and IBP Co. Limited,
- (ii) Bongaigaon Oil Refinery Ltd., Refinery Laboratory, P O New Bongaigaon, Distt. Kokrajhar, Assam,
- (iii) Chennai Petroleum Corpn Ltd , Refinery Laboratory, Manali, Chennai-600019, Tamil Nadu,
- (iv) Kochi Refinery Ltd , Refinery Laboratory, Post Ambalamugal, Kochi-682302, Kerala,
- (v) Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. Refinery Laboratory, Kuthethoor, P.O.-Katipalla, Moodapadav, P B.No 2, Mangalore 574149, Karnataka,
- (vi) Numallgarh Refinery Limited, Refinery Laboratory, Numallgarh, Assam; and
- (vii) Reliance Petroleum Ltd Refinery Laboratory, Moti Khavdi (VIII), Digvijayagram (PO) Jamnagar (Distt.)-361140, Gujarat.

2. Government Laboratories

- (i) Director of Alworthiness, Civil Aviation Deptt Laboratory, Block, II/III East, R K Puram, New Delhi-110066
- (ii) National Test House, 11/1, Judges Court Road, Allpore, Calcutta-700027
- (iii) National Physical Laboratory, Pusa, New Delhi-110012,
- (iv) Chemical Testing and Analytical Laboratory, Industries and commerce Department, Government of Tamil Nadu, Guindy, and

3. Defence Laboratories

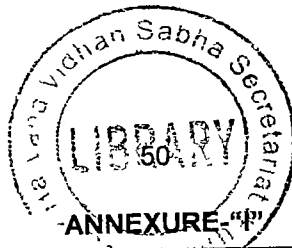
- (i) Chief Controlrate of Materials, Controlrate General of Stores Laboratory, IGS Kanpur, P.B No -229, Kanpur;
- (ii) Inspectorate General of stores Laboratory (I.G.S.L), DGI Complex, Chennai-600114,
- (iii) Inspectorate General of Stores Laboratory, DGI Complex, Hastings, Calcutta-700022, and
- (iv) Inspactorate General of stores Laboratory, DGI Complex Vikhroll, Mumbai-400083.

4. Other Laboratories

- (i) Central Power Research institute, Bangalore,
- (ii) Fuel Testing Laboratory, Society for Petroleum Laboratory, B-14, Sector-62, Noida, U P ,
- (iii) Indian Institute of Petroleum, Dehra Dun-248005,
- (iv) Indian Institute of Technology, Guindy Chennai,
- (v) Indian Institute of Technology, Hauz Khas, New Delhi,
- (vi) Indian Institute of Technology, Powai Mumbai,
- (vii) Indian Institute of Technology, Kharagpur,
- (viii) Regional Research Laboratory Uppal Road, Hyderabad-500007,
- (ix) Ramedv Baba Engineering College, Kalol Road, Nagpur 440013, Maharashtra, and
- (x) Lakshmi Narayan Institute of Technology, Amravati Road, Nagpur 440010, Maharashtra

ANNEXURE-"H"
DISTRICT/COMPANY WISE TOTAL NUMBER OF PETROL PUMPS
FUNCTIONING
IN THE STATE AS ON 31.12.2016.

Sr. No.	District	IOC	BPC	HPC	ESSAR	RELIANCE	TOTAL
1.	Ambala	48	19	34	0	1	102
2.	Bhiwani	99	29	56	7	3	194
3.	Fardabad	41	17	20	2	0	80
4.	Fatehabad	44	13	28	4	4	93
5.	Gurugram	72	25	38	7	0	142
6.	Hisar	92	23	49	2	1	167
7.	Jind	64	11	27	7	2	111
8.	Jhajjar	55	18	26	5	0	104
9.	Karnal	98	21	42	13	4	178
10.	Kaithal	54	14	39	13	2	122
11.	Kurukshetra	52	17	30	1	3	103
12.	Mahendergarh	74	16	27	5	4	126
13.	Mewat	49	11	20	6	3	89
14.	Panipat	69	9	26	6	0	110
15.	Panchkula	28	10	15	1	0	54
16.	Palwal	53	13	22	2	2	92
17.	Rewari	84	30	35	6	3	158
18.	Rohtak	58	19	26	2	0	105
19.	Sirsa	107	26	51	6	4	194
20.	Sonepat	65	26	33	3	3	130
21.	Yamuna Nagar	67	23	38	3	2	133
	Total	1373	390	682	101	41	2587



Type of Distributorship area	Population as per census 2011	Refill Ceiling Limit per month	Refill Sale per month for Feasibility limit
Sheheri Vitrak	Cities with Population > 40 lakh	20,000	10,000
	Cities with 20 to 40 lakh Population	15,000	7,500
	Cities with 10 to 20 lakh Population	12,000	6,000
Rurban Vitrak	Towns with < 10 lakh population	10,000	5,000
Gramin Vitrak	Village/Cluster of Village	5,000	2,500
Durgam Khetriya Vitrak	Village/Cluster of Village	1,500	600

ANNEXURE-"J"

Sr No.	As on 31 12 2016	No. of give it up 31 12 2016	No. of give it up 31.12 2016	No of give it up 31 12 2016	
		IOCL	BPCL	HPCL	Total
1.	Ambala	1940	4421	2273	8634
2	Bhiwani	5057	4531	6895	16483
3.	Faridabad	20633	15070	12809	48512
4.	Fathehabad	3314	4806	408	8528
5.	Gurgaon	23621	9780	15475	48876
6.	Hissar	8614	3993	1755	14362
7	Jhajjar	7097	5306	4470	16873
8	Jind	4355	2615	4527	11497
9	Kaithal	1303	0	666	1969
10.	Karnal	7292	2366	3824	13482
11	Kurukshetra	1035	8248	2828	12111
12	Mahendergarh	4510	753	1854	7117
13	Mewat	1478	0	2528	4006
14	Panchkula	1941	4378	1931	8250
15	Panipat	7851	2756	8830	19437
16	Rewari	10069	4585	0	14654
17.	Rohtak	13072	7833	4964	25869
18	Sirsa	2218	4502	4293	11013
19	Sonepat	4489	6662	2364	13515
20	Yamuna Nagar	3349	9172	994	13515
21.	Palwal	1388	1512	10233	13133
	Total	134626	103289	96921	331836

ANNEXURE-"K"
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
ORDER

New Delhi, the 26th April, 2000

G S R 487(E)- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely -

- 1 Short Title and Commencement - (1) This order may be called the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply of Distribution) Order, 2000
- (2) it extends to the whole of India
- (3) It shall come into force on the date of its publication if the Official Gazette
- 2 Definitions- In this Order, Unless the context otherwise requires-
 - (a) Chief Controller of Explosives shall have the same meaning assigned to it in the Explosives Act, 1884 (4 of 1884)
 - (b) "Consumer" means a registered person firm company institution, association of persons, co-operative society or organisation, who has been granted liquefied petroleum connection or supply, either in bulk or cylinder, by a distributor or a Government oil company or a parallel marketeer,
 - (c) "cylinder" means a metal container Utilizer for storing liquefied petroleum gas conforming to the specification laid down in Schedules II and III
 - (d) "Delivery Person" a person engaged by a distributor of Government oil company or a parallel marketeer to deliver liquefied petroleum gas in cylinder to consumers,
 - (e) "distributor" means a person firm association of persons, company institution, organisation or a co-operative society appointed by a Government Oil company or parallel marketeer and engaged in the business of purchase, sale or storage for sale of liquefied petroleum gas in cylinder to consumer on the basis of an agreement with a Government Oil Company or a parallel marketeer, as the case may be,
 - (f) "gas cylinder valve" means a valve which is fitted to a cylinder
 - (g) "Government Oil Company" means
 - (1) Bharat Petroleum Corporation Limited
 - (2) Bongaigaon Refinery and Petrochemicals Limited
 - (3) Cochin Refineries Limited
 - (4) Gas Authority of India Limited
 - (5) Hindusthan Petroleum Corporation Limited
 - (6) Indian Oil Corporation Limited

- (7) Indo-Burma Petroleum Company Limited
- (8) Chennai Petroleum Company Limited
- (9) Numaligarh Refinery Limited
- (10) Oil India Limited
- (11) Oil and Natural Gas Corporation Limited or
- (12) any other Government Company or a statutory body or a company or a firm, declared as such by notification in the Official Gazette, to be a "Government Oil Company by the Central Government, for the purposes of this Order
- (h) "Indian Standard" shall have the same meaning as assigned to it in clause g of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).
- (i) "Liquefied Petroleum Gas (or LPG) means a mixture of light hydrocarbons which may include propane, isobutane, normal butane, butylenes etc, which are gaseous at normal ambient temperature and atmospheric pressure but may be condensed to liquid state at normal ambient temperature by the application of pressure and which conforms to Indian Standard specification number IS 4576,
- (j) "parallel marketer" means any person, firm company institution, association of person, co-operative society or organisation carrying on any or all of the business of importing storing, bottling, marketing, distributing and/or selling liquefied petroleum gas under the parallel marketing system,
- (k) "parallel marketing system" means the system other than the public distribution system, under which a parallel marketer carries on any or all of the business of importing, storing, bottling, distribution or selling in bulk or in retail, packed or filled in cylinder, liquefied petroleum gas under his own arrangement,
- (l) "public distribution system" means the system of distribution marketing or selling of liquefied petroleum gas by a Government oil Company at the Government controlled or declared process through a distribution system approved by the Central or a State Government;
- (m) "pressure regulator" means the equipment used for regulating the flow and pressure of liquefied petroleum gas from a cylinder to a gas stove;
- (n) "Schedule" means a Schedule appended to this order,
- (o) "seal" means seal put on the cap of the valve of the cylinder of the purpose of sealing a cylinder after it has been filled with liquefied petroleum gas;
- (p) "storage point" means the premises licensed by the Chief Controller of Explosives,

- (q) "transporter" means a person authorised by a Government Oil Company parallel marketeer or a distributor for transportation of LPG in bulk or in cylinders and also of empty or defective cylinders,

3. Restriction on unauthorised possession, supply and consumption of liquefied petroleum gas-

- (1) A person having a connection for liquefied petroleum gas under the public distribution system, shall not-
- (a) Possess more than one connection of liquefied petroleum gas granted under the public distribution system

Provided that the Central Government or the Chief Executive Officer of a Government Oil Company, may sanction more than one connection of liquefied Petroleum gas under the public distribution system in favour of any person, keeping in view the difficulty and hardship experienced by such person in obtaining supplies of the LPG

4. Restriction on storage and transport of liquefied petroleum gas-

- (1) No person shall-
- (a) Fill any cylinder with liquefied petroleum gas or transfer liquefied petroleum gas from one cylinder to another cylinder or from one container to another container unless authorised by the Chief Controller of Explosives;
- (b) Transport or store a cylinder filled with liquefied petroleum gas except in an upright position;

(c)

5. Restriction on sale or distribution of liquefied petroleum gas below or in excess of the standard weight- No Government Oil Company, distributor or parallel marketeer shall supply, sell or distribute to a consumer liquefied petroleum gas in cylinders which contains less than or in excess of the weight of liquefied petroleum gas specified in the Schedules II and III or as indicated on the cylinder

6. Prohibition on carrying unauthorised business of selling LPG-

No person other than a Government Oil Company, a parallel marketeer or a distributor shall be engaged in the business of selling liquefied petroleum gas to the consumer.

7. Possession, supply or sale of liquefied petroleum gas equipments.-

- (1) No person shall-
- (a) Supply or sell filled or empty cylinder, gas cylinder valve and pressure regulator to any person other than a Government Oil Company or a parallel marketeer,

8. Display of stock and price of liquefied petroleum gas-

Every distributor shall prominently display the stock and price of the liquefied petroleum gas at a conspicuous place of the business premises including the storage point showing-

- (i) The opening balance of filled, empty and defective cylinders and regulators;

9. Procurement, storage and sale of liquefied petroleum gas by a distributor-

- (a) No distributor having stock of liquefied petroleum gas at the business premises, including storage point, shall unless otherwise directed by a Government Oil Company or a parallel marketeer, refuse to sell LPG on any working day during working hours, to the consumer registered with that distributor

10. Maintenance of register, account books by a distributor:-

- (a) Every distributor shall maintain proper accounts of daily purchase, sale and storage of liquefied petroleum gas at the business premises indicating therein-
 - (i) the opening stock of the filled empty and defective cylinders,
 - (ii) the number of filled empty and defective cylinders received during the day;

11. Assessment and Certification Rating of parallel marketeers.

- (1) (a) No parallel marketeer shall commence any activity, such as, importing, storing, transporting, bottling, marketing, distribution, sale or any activity incidental thereto, relating to the business of liquefied petroleum gas without obtaining a rating certificate for his capability infrastructure network and readiness to carry out professed business and deliver goods and services promised provision for adequate safety backup for transportation, accident relief during transportation and attending to emergency complaints of consumers by an agency given in Schedule-IV on the basis of its evaluation and rating
- (b) The rating certificate shall be issued in the form as specified in Schedule-V, and as per the forwarding letter given in Schedule-VI.
- (2) Every parallel marketeer announcing details of his activity or inviting offers of any kind in the field of import, transport, marketing, bottling, distribution or sale of liquefied or by any other means of communication or advertising shall indicate the rating awarded to him in words i.e. Good, Satisfactory, Low-risk, High Risk which ever is applicable, and prominently publish the rating certificate, as given by the rating agency.

12. Maintenance of records and furnishing of information by parallel marketeer,

Every parallel marketeer before commencing the import, transportation, bottling, marketing, distribution or sale of liquefied petroleum gas shall intimate to the Ministry of Petroleum and Natural Gas all or any of the above activities which he intends to undertake, specifying therein capability to do so, and any other relevant particulars

13. Power of entry, search and seizure.-

Any Officer of the Central or the State Government not below the rank of Inspector duly authorised by a general or a special order, by the Central Government of the State Government, as the case may be or any officer of a Government oil Company not below the rank of sales Officer, authorised by the Central Government, may with a view to securing due compliance of this Order or any other order made thereunder,

14. Overriding effect of the Order.-

The provisions of this Order shall have overriding effect notwithstanding anything contained in any Order made by a State Government or an Union Territory Administration.

15 Power to exempt.-

The Central Government may if it considers necessary for avoiding any hardship or in consideration of the public interest, by a notification in the Official Gazette, exempt any person or class or person from all or any of the provisions of this Order, either generally or for specific purpose and subject to such conditions as may be specified in the notification

16 Repeal and saving.-

The Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 1993 is hereby repealed

Provided that such repealed shall not effect

- (a) The previous operation of the said order or anything duly done or suffered therein, or
- (b) Any right, privilege, obligation or liability acquired in respect of any offence committed against the said Order,

Schedule-I

(See clause 3(4))

(for Government Oil Companies)

- 1 Forced sale of stove/Hotplates the consumers
- 2 Recovery of unauthorised charges from applicant at the time of registration/release of new connection
- 3 Supply of partially used cylinder/pillering product form Cylinder/Cylinders with pilfered product to LPG consumer
4. Unauthorised and/or out of turn relese of new LPG connections.
- 5 Unauthorised diversion of domestic cylinder for non domestic of LPG
- 6 Acceptance of fake documents including termination vouchers and transfer Termination Vouchers.
- 7 Possession of spurious LPG equipment
- 8 Induciton of spurious LPG equipment and/or replacement by a spurious aquipment
- 9 Manipulation of mandatory records
10. Non-home delivery of LPG refill supplies to consumer and/or not giving rebate on non-home delivery to LPG consumer
11. Overcharging by distributor on LPG refill supplis, installation charges mechanic charges and/or any other authorised by the Government Oil Company
- 12 Refusal to register requests for new connection and/or double bottle connection

Annexure-"M"

DISTRICT WISE LPG DISTRIBUTORS IN HARYANA AS ON 31.12.2016.

Sr. No.	Name of District	IOC	BPC	HPC	TOTAL
1	Ambala	12	14	3	29
2	Bhiwani	5	14	5	24
3	Faridabad	15	14	3	32
4	Fatehabad	5	12	1	18
5	Gurgaon	21	11	6	38
6	Hisar	14	10	6	30
7	Jhajjar	7	1	8	16
8	Jind	5	3	6	14
9	Kaithal	13	0	2	15
10	Karnal	24	3	4	31
11	Kurukshetra	10	8	2	20
12	Mahendergarh	11	1	3	15
13	Mewat	6	0	2	8
14	Panchkula	1	3	4	8
15	Panipat	9	2	7	18
16	Palwal	11	5	4	20
17	Rewari	18	5	0	23
18	Rohtak	10	7	8	25
19	Sirsa	9	9	7	25
20	Sonipat	5	10	4	19
21	Yamuna Nagar	10	9	3	22

Annexure-"N"

DETAILS OF LPG CHECKING FROM 04/2015 TO 11/2016

SR. NO.	DISTRICT	No. of LPG Dealer	No. of inspections carried out	No. of discrepancies	Action taken against LPG Dealer
1	Ambala	29	26	Nil	Nil
2	Bhiwani	24	30	Nil	Nil
3	Fardabad	32	90	Nil	Nil
4	Fatehabad	18	5	Nil	Nil
5	Gurgaon	38	9		
				Stock Register is not attested	Warning issued (M/s Pataudi Indane Gas Service, Pataudi, Gurgaon)
				Stock board not filled Stock Register is not attested	Warning issued (M/s Shaheed Shyam Singh, Gas Agency, Farukhnagar, Gurgaon)
				Weight shortage in 10 cylinder about 100-200 gm. 25 commercial cylinder (19.2 Kg) is found short as per record	Warning issued (M/s Madhu Gas Service, Gurgaon (BPC))
				6 excess cylinder was found godown	Warning issued (M/s Anand Enterprises Gas Agency, Gurgaon (IOC))
				Rate & stock Board not filled. Breake Measurement instrument was found 63 commercial cylinder (19.2 Kg.) was found short	Warning issued (M/s Jagriti Gas Service, Gurgaon (BPC))
				Sale and stock board register	Warning issued (M/s Mata Sheetla Gas Service,

				was not found at the time of PV Shortage of weight in O2 cylinders	Gurgaon (IOC)
				Shortage of 5 filled cylinder and 2 empty is found in excess. Shortage of 3 commercial cylinder was found. Rate and stock board not filled.	Warning issued (M/s Chand Gas Service, Gurgaon (BPC))
				Shortage of 4 filled commercial cylinder and 2 empty cylinder was found	Warning issued (M/s H P Gas Service, Manesar, Gurgaon (HPC))
				Rate and stock board was not found, fire extinguisher was not validated	Warning issued (M/s Mahalaxmi Gas Service, Gurgaon (IOC))
6	Hisar	30	0	Nil	Nil
7	Jind	14	15	Checking sale & stock	Case sent to Oil Company M/s Shiv HP Gramin Gas Agency, Jind
8	Jhajjar	16	25	Nil	Nil
9	Karnal	31	17	Case forward to oil Company	Case under consideration to Oil Company (M/s Jeet gas Agency)
10	Kaithal	15	33	6 cylinder short	Warning issued (M/s neelam gas Agency)
11	Kurukshetra	20	36	Nil	Nil
12	Mewat	8	20	Nil	Nil
13	Namaul	15	31	Under weight	Case forwarded to Oil Company (M/s Krshan gas Agency)
14	Panipat	18	7	Nil	Nil

15	Panchkula	8	44	Nil	Nil
16	Palwal	20	72	Nil	Nil
17	Rewari	23	44	Nil	Nil
18	Rohtak	25	9	Nil	Nil
19	Sirsa	25	18	Nil	Nil
20	Sonepat	19	9	Nil	Nil
21	Yamuna Nagar	22	20	Nil	Nil
TOTAL		450	560		

Annexure-"O"

Statement showing District wise details of ineligible Rural BPL Households deleted from BPL list 2007

SR.NO.	DISTRICT	Ineligible Rural BPL households deleted (in Nos)
1	Ambala	3878
2	Bhiwani	10248
3	Faridabad	1394
4	Fatehabad	7720
5	Gurgaon	874
6	Hisar	5409
7	Jhajjar	4054
8	Jind	1829
9	Kaithal	5650
10	Karnal	5052
11	Kurukshetra	294
12	Mahendergarh	1516
13	Mewat	5153
14	Panchkula	4932
15	Panipat	4199
16	Palwal	4833
17	Rohtak	81
18	Rewari	1452
19	Sirsa	3469
20	Sonapat	8297
21	Yamuna Nagar	2818
TOTAL		83062

Annexure-"P"

STATE URBAN DEVELOPMENT SOCIETY HARYANA
DISTRICT WISE COMPARASION OF URBAN BPL FIGURES

SR. NO.	DISTRICT	BPL Families (updated in 2009)	No. of deleted ineligible urban BPL families during re-survey process in March 2012	Balance Urban BPL families (March 2012)
1	Ambala	31204	1764	29440
2	Bhiwani	33317	5233	28084
3	Fardabad	65650	5294	60358
4	Fatehabad	14250	5673	8577
5	Gurgaon	23876	7946	15930
6	Hisar	39046	3786	35260
7	Jhajjar	15546	5322	10224
8	Jind	25056	1166	23890
9	Kaithal	24294	9903	14391
10	Karnal	36880	13782	23098
11	Kurukshetra	16416	2364	14052
12	Narnaul	9531	885	8646
13	Nuh	8681	5791	2890
14	Panchkula	13181	9207	3974
15	Panipat	42383	26145	16238
16	Palwal	14096	2490	11606
17	Rohtak	26132	79	26053
18	Rewari	17046	283	16763
19	Sirsa	31897	2077	29820
20	Sonapat	29681	12843	16838
21	Yamuna Nagar	29181	1601	27580
TOTAL		547344	123634	423710

Annexure-"Q"
DISTRICT WISE BPL FAMILIES UPTO 31.12.2014

SR. NO.	DISTRICT	SBPL	CBPL	AAY	H/LESS	TOTAL
1	Ambala	33004	24158	14218	672	72052
2	Bhiwani	30627	36637	17305	2	84571
3	Faridabad	43624	16593	7589	167	67973
4	Fatehabad	24075	14548	11067	558	50248
5	Gurgaon	13483	12516	9165	424	35588
6	Hisar	17554	46624	18366	8	82552
7	Jhajjar	35028	15105	18179	29	68341
8	Jind	5180	15932	8776	41	29929
9	Kaithal	24111	31090	13017	51	68269
10	Karnal	21611	19321	17145	1472	59549
11	Kurukshetra	9598	26939	12417	332	49286
12	Narnaul	12293	19992	16065	1131	49481
13	Mewat	14424	13970	10820	57	39271
14	Panchkula	4427	4500	2388	851	12166
15	Panipat	7481	19218	10492	823	38014
16	Palwal	7724	28035	9194	0	44953
17	Rohtak	17626	22038	5919	0	45583
18	Rewari	19455	14247	13592	152	47446
19	Sirsa	18204	26769	22473	0	67446
20	Sonapat	11874	33505	10572	6	55957
21	Yamuna Nagar	20792	33428	9381	1045	64646
TOTAL		392195	475165	258140	7821	1133321

Annexure-"R"

Details of BPL/AAY Ration Cards issued during the tenure of present Govt.

SR. NO.	DISTRICT	The No. of yellow and pink Ration cards have been issued during in the tenure of present Govt.	Total No. of BPL Ration Cards		Total No. of AAY Ration Cards	
			Urban	Rural	Urban	Rural
1	Ambala	17	4	13	0	0
2	Bhiwani	47	1	46	0	0
3	Faridabad	0	0	0	0	0
4	Fatehabad	52	12	40	0	0
5	Gurgaon	1359	547	812	0	0
6	Hisar	3	1	2	0	0
7	Jind	220	140	80	0	0
8	Jhajar	168	150	0	0	18
9	Karnal	0	0	0	0	0
10	Kaithal	20	6	14	0	0
11	Kurukshetra	1703	373	1200	18	112
12	Mewat	0	0	0	0	0
13	Narnaul	169	17	152	0	0
14	Panipat	36	17	19	0	0
15	Panchkula	358	85	273	0	0
16	Palwal	0	0	0	0	0
17	Rohtak	7	3	4	0	0
18	Rewari	194	83	111	0	0
19	Sirsa	70	8	62	0	0
20	Sonapat	288	68	220	0	0
21	Yamuna Nagar	322	0	0	91	231
TOTAL		5033	1515	3048	109	361

Annexure-"S"

SR. NO.	DISTRICT	AAY	SBPL	CBPL	(AAY+SBPL+C BPL)
		RATION CARDS	RATION CARDS	RATION CARDS	RATION CARDS
1	Ambala	15155	33247	24004	72406
2	Bhiwani	16756	28771	35853	81380
3	Fardabad	6205	41729	14032	61966
4	Fatehabad	11298	24574	13616	49488
5	Gurgaon	9430	13502	12294	35226
6	Hisar	17519	16749	44326	78594
7	Jhajar	8643	5744	15232	29619
8	Jind	17700	35671	13223	66594
9	Kaithal	18110	22021	18210	58341
10	Karnal	12772	23306	30937	67015
11	Kurukshetra	12700	10779	27284	50763
12	Mahendergarh	16965	11870	20339	49174
13	Mewat	10779	14705	13501	38985
14	Palwal	10049	6588	19285	35922
15	Panipat	8965	11998	27067	48030
16	Panchkula	2686	3944	4309	10939
17	Rewari	13885	19784	14856	48525
18	Rohtak	5605	15787	21480	42875
19	Sirsa	21159	18096	26657	65912
20	Sonipat	10139	19963	24598	54700
21	Yamuna Nagar	10022	19608	34139	63769
GRAND TOTAL		256545	398436	455242	1110223

Annexure-“U”

The size of bricks as per P.W D. specification is as under:-

1) Size of Bricks:-

22.86 Cm x 11.11 Cm x 6.83 Cm

A tolerance upto + 6.5 mm in length + 3.00 mm in width and + 3.00 mm in thickness shall be permitted. A frog 65 mm deep shall be provided on the upper face.

2) Size of Brick Tiles:-

(a) Tiles for flooring, tile facing & tile brick masonry size 22.86 Cm x 11.43 Cm x 3.81 Cm.

(b) Tiles for 1st class Mud roofing (not in common use as on today)

(c) Tiles for second class Mud roofing for flooring and canal lining

Size 30.48 Cm x 15.24 Cm x 5.08 Cm

Permissible tolerance limit in size of brick tiles + 6.5 mm in length + 3.00mm for width + 1.5 mm in thickness

District wise tentative stock of wheat as on 15.12.2016 (Food and Supplies Department)

Sr. No.	Name of District	2016-17		Grant Total
		Covered	Open	
1	Ambala	2604	6	2620
2	Bhiwani	0	0	0
3	Faridabad	0	0	0
4	Fatehabad	5850	0	5850
5	Gurgaon	0	0	0
6	Hisar	18074	0	18074
7	Jind	3397	0	3397
8	Jhajar	6544	0	6544
9	Karnal	54948	17653	72601
10	Kaithal	42876	2145	45021
11	Kurukshetra	17437	0	17437
12	Namaul	3437	0	3437
13	Panipat	10047	0	10047
14	Palwal	4416	0	4416
15	Rewari	0	0	0
16	Rohtak	0	0	0
17	Sirsa	40377	0	40377
18	Sonapat	954	0	954
19	Yamuna Nagar	19247	388	19635
	TOTAL	230218	20192	250410

Observations/Recommendation of the Committee.

- 1 The Committee orally examined the representatives of the Department and get ensured that the quality of the food to be given to BPL card holders must be checked properly before distribution
- 2 During the oral examine the Committee has not satisfied with the reply regarding the working of fair price shops Therefore, the Committee recommended the regular checking of fair price shops by the Department and steps be taken to increase the income of fair price shops holders and they should also be permitted to sell more item to eradicate corruption
- 3 During the oral examination of the representatives of the Department, the committee noticed that some person are holding more than one depot and recommended the Department to check the multiple holding of depots and also to make ensure that one person holds one depot only
- 4 During the oral examine the Committee recommended that necessary steps be taken to ease the persons of granting license for setting up of Brick kilns, the documents process should be minimized and the collection centre for documents and NOC should be made at District level So that the corruption is stopped
- 5 During the oral examine the Committee recommended that steps be taken to parpose ration cards as similar to smart cards by having the details of the card holder on one side and details of family on the other side
- 6 During the oral examine the Committee recommended that the Department should take necessary steps for filling up the vacant post and new recruitments so that the work of the Department does not suffer and no inconvenience is caused
7. During the oral examination the Committee noticed that the terms and conditions set up by the Government are not being followed properly in the distribution of Ration from the Depots Therefore, the Committee recommends that the Department should take necessary action against those who are not following the proper procedure and terms and conditions The money by the Depot holders must be deposited by 7th of every month and ration be delivered to them by 10th and should be distributed to the ration card holders by 30th of every month
- 8 During the oral examination the Committee recommended that all the eligible families who have not been issued BPL Cards should be issued at the earliest
- 9 During the oral examination the Committee recommended that a consumer should be allowed to transfer his LPG Gas agency/company to another Gas agency/company according to his satisfaction in his town/village



© 2016

Published under the authority of the Haryana Vidhan Sabha
and printed by the Controller, Printing and Stationery
Department, Haryana, Chandigarh

